www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 169 || लखनऊ
रविवार
20 सितम्बर 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
मौसम
सूर्योदयः 05:53
सूर्यास्तः 06:05
अधिकतमः 33°00
न्यूनतमः 26°00

पेज 07

विशेष समाचार
सत्ता से संघर्ष तक: ममता ... >>पेज 04
5 लाख रुपए में श्रीराम और ... >>पेज 06
बेटी राहा का चेहरा छिपाती दिखीं ...

पहले चाचा-भतीजे नौकरियों पर डकैती डालते थे, आज उपदेश दे रहे मैं नौकरी देता जाऊंगा, वह गिनते जाएं : योगी

योगी ने कहा- यूपी के पास क्या नहीं था? कभी यूपी देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य था, लेकिन राजनीतिक संक्रमण के दौर में यूपी की पहचान का संकट पैदा हो गया था। कोई बेटी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। कोई व्यापारी व्यापार करने को तैयार नहीं था। आज भी यूपी वही है और चुनौतियां भी वही हैं। कि उन्होंने चुनौती को समस्या माना, हमने चुनौती को अवसर माना।

नियुक्तियां

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सीएम योगी ने शनिवार को लखनऊ में अखिलेश और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- पहले नौकरियों में डकैती डालने के लिए चाचा-भतीजे की जोड़ी बेखौफ निकल पड़ती थी। आज उपदेश की भूमिका में हैं। 2027 के बाद उपदेश भी नहीं रह पाएंगे। सीएम ने कहा- 2017 से पहले UPPSC का चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया गया, जो खुद योग्य नहीं था। चेयरमैन बनने के बाद उसने गदर मचाई। इसके चलते युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। कोर्ट ने कहा- उसे जेल भेजो, जिंदगी भर सड़ाओ। हमने ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था ही खत्म कर दी। पहले ऐसी कई भर्तियां हुईं, जिनमें जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था, उन्हें भी नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। यह अराजकता की पराकाष्ठा थी। यूपी होमगार्ड में 42 हजार नियुक्तियां होने जा रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगले छह महीने में आने वाले परिणामों में 25 से 30 हजार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। शिक्षा चयन आयोग से 20 से 25 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी। यूपी लोक सेवा आयोग से 15 से 16 हजार नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो लोग ये काम नहीं कर पाए, वे आज सवाल उठा रहे हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)

818 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर बांटे सीएम ने।

योगी ने कहा-पहले बिना परीक्षा दिए ही नौकरी मिल जाती थी। विज्ञापन जारी होते ही ठेके बांट दिए जाते थे और धंधा शुरू हो जाता था। जिन्होंने 2017 से पहले नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, वे नोट कर लें कि अगले 6 महीने में एक लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। वे गिनते रहें, हम नौकरियां देते जाएंगे।

जो लोग ये काम नहीं कर पा रहे, वो आज सवाल उठा रहे

सीएम ने कहा- जो प्रदेश सबसे गरीब माना जाता था, वही आज स्टेट रेवेन्यू सरप्लस है। हम पिछड़े नहीं हैं। इन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने जो संकट खड़ा किया था, उससे उन्हें उबारने के लिए हमारी सरकार ने मिशन रोजगार शुरू किया। जो लोग ये काम नहीं कर पाए, वे आज सवाल उठा रहे हैं।

भाई-भतीजों को बैठाकर आयोग को बदनाम किया

सीएम ने कहा- भर्ती बोर्ड और आयोगों में भाई-भतीजों को बैठाकर भर्ती प्रक्रिया को बदनाम कर दिया गया था। एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं होती थी। अब भर्ती बोर्ड और आयोग शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं। अब तक साढ़े नौ लाख युवाओं को जॉइनिंग लेटर बांटे जा चुके हैं।

यूपी को उपद्रव प्रदेश बनाने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी

सीएम ने कहा- 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। आज यूपी में बाहर से निवेशक आ रहे हैं। जब सरकार ईमानदारी से काम करे और बिना भेदभाव के सभी को अवसर दे, तभी ऐसे बदलाव आते हैं। जिन्होंने उत्सव के प्रदेश को उपद्रव का प्रदेश बना दिया, उन्हें यूपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह केवल गलती नहीं थी, बल्कि शरारत थी।

2014 से पहले आयुष की कोई खास पहचान नहीं थी। पीएम मोदी ने नया मंत्रालय बनाकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को पहचान दी। 2014 से पहले कोई यह नहीं सोचता था कि आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिग्री ली जाए। अब आयुष विश्वविद्यालय बन रहे हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट का तीसरा रनवे आज से शुरू होगा

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट का तीसरा रनवे 11R/29L कल से ऑपरेशन में आ जाएगा। रनवे को इसी साल फरवरी में रिहैबिलिटेशन के लिए बंद किया गया था। करीब 7 महीने बाद इसे दोबारा चालू किया जा रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने शनिवार को बताया कि रनवे को चालू करने से पहले सभी जरूरी निरीक्षण, वैलिडेशन और रेगुलेटरी मंजूरियां ली गईं।

नए रनवे पर रैपिड एक्जिट टैक्सीवे (RET) बनाया गया है। जिस पर लैंडिंग के बाद विमान की स्पीड कम होते ही यह मुख्य रनवे से बाहर निकल सकता है।

इससे विमान जल्दी रनवे खाली करेगा। अगले विमान के लैंडिंग या टेकऑफ के लिए रनवे जल्दी उपलब्ध होगा।

इसका उद्देश्य सुरक्षा, ऑपरेशन और रेगुलेटरी से जुड़ी सभी जरूरी शर्तें पूरी करना था।

इंदौर में राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज'

कहा- सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछें

संबोधन

तमसा संकेत, एजेंसी

इंदौर। राहुल गांधी ने इंदौर में 'छात्रों की गूंज' को संबोधित किया। कार्यक्रम के 5वें एडिशन में उन्होंने 'सिस्टम बनाम स्टूडेंट्स' विषय पर करीब 60 मिनट बात की। कार्यक्रम के लिए IDA ग्राउंड पर 20 से 25 हजार युवा पहुंचे। छात्रों से सवाल-जवाब के दौरान राहुल ने कहा- सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स सवाल पूछें, इसलिए वह अंधभक्त पैदा करता है। उन्होंने कहा- छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ गया है, हालांकि कुछ जगह

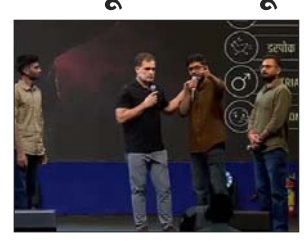

कैंडिडेट्स की भी गलती है। इस पर सामने बैठे छात्रों ने जवाब दिया- सर, हम सिस्टम से हार गए। कांग्रेस ने बताया कि कार्यक्रम के लिए करीब 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। इसकी अनुमति 31 शर्तों के साथ मिली। राहुल ने कार्यक्रम के बाद डोम के अंदर मौजूद छात्रों के साथ सेल्फी ली।

>> (शेष पेज 06 पर)

'रोजगार बढ़ाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही सरकार'

पीएम मोदी ने 51 हजार युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र

रोजगारमेला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 20वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं, जब देश बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।

>> (शेष पेज 06 पर)

पीएम मोदी ने कहा- देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं।

फास्ट न्यूज

केरल नौसेना अकादमी से बांग्लादेशी गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम। केरल की एझिमाला नौसेना अकादमी में फर्जी कागजात से भारतीय नागरिक बनकर काम कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 साल के बिप्लब सोरेन के रूप में हुई है। वह अकादमी के लॉन्ड्री सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था।

सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर सवाल उठाए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी से शराब की लत और जहरीली शराब से होने वाली मौतें खत्म नहीं होतीं। कोर्ट ने कहा कि जबरन शराबबंदी, शराब की समस्या का समाधान नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि गुजरात में दशकों से शराबबंदी लागू हैं, लेकिन जहरीली शराब से हो रही मौतें नहीं रुकीं। मेथनॉल मिली शराब से 10 बड़े हादसों में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट 18 सितंबर को महाराष्ट्र पॉइजन्स रूल्स, 1972 के नियम 18A और 18B रद्द करने का फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।

हामिद अंसारी ने पूर्व पीएम नेहरू की बात दोहराई

नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का एक पुराना बयान दोहराते हुए कहा कि भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से नहीं, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से था। अंसारी ने यह बात तीसरे एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में कही। यह कार्यक्रम अब्दुल गफूर नूरानी के जीवन और काम पर आयोजित किया गया था।

रेजीनगर में ममता के प्रत्याशी का यू-टर्न हुआ

नामांकन वापस लेने का फैसला बदला

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के पहले सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। रेजीनगर में TMC उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने शनिवार सुबह 10 बजे चुनाव से हटने का ऐलान किया, लेकिन करीब 3 घंटे बाद ही दोपहर एक बजे यूटर्न ले लिया। रबीउल ने सुबह हटने का ऐलान करते वक्त पार्टी का पुराना चुनाव चिह्न 'जोड़ा घासफूल' नहीं मिलने और नया चिह्न 'फुटबॉल प्लेयर' मिलने को इसकी वजह बताया था। हालांकि, ममता बनर्जी से बातचीत के बाद रबीउल ने कहा, ₹मैं चुनाव लड़ूंगा।₹ इससे एक दिन पहले नंदीग्राम में भी ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया था। रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और 9 अक्टूबर को मतगणना होगी।

>> (शेष पेज 06 पर)

डूसू चुनाव में एबीवीपी की हुई बड़ी जीत

17 साल बाद कोई निर्दलीय भी जीता, उपाध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा 30 हजार+ वोट मिले

छात्रराजनीति

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन पदों पर जीत हासिल की। ABVP के यश डबास अध्यक्ष बने हैं। वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्यराज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता। उन्हें 30 हजार से ज्यादा वोट मिले। पिछले 17 सालों में यह पहली बार है जब DUSU के केंद्रीय पैनल में कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीता हो। इससे पहले 2009 में निर्दलीय मनोज चौधरी और 1991 में निर्दलीय राजीव गोस्वामी DUSU अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI को एक भी पद हासिल नहीं हुआ। DUSU चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और 1,51,519 छात्रों में से 61,312 ने मतदान किया। शौकीन दिल्ली के पीरागढ़ी के रहने वाले हैं। उनके पिता बस कंडक्टर हैं और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है।

>> (शेष पेज 06 पर)

एनएसयूआई के नाराज कार्यकर्ताओं का साथ मिला, जीत की 3 वजहें...

- *NSUI से टिकट नहीं मिला, फिर भी मैदान नहीं छोड़ाः शौकीन 4 साल NSUI से जुड़े रहे और छात्र राजनीति में एक्टिव थे। उन्होंने उपाध्यक्ष पद का टिकट मांगा था। संगठन की ओर से उनका नामांकन भी कराया गया, लेकिन बाद में उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। शौकीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।*
- *ABVP-NSUI से अलग अपनी पहचानः वे पहले से छात्र राजनीति में सक्रिय थे। इसलिए चुनाव में उनकी पहचान सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं, बल्कि कैंपस में सक्रिय छात्र नेता की भी थी। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो NSUI के नाराज कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया।*
- *छात्रों के स्थानीय मुद्दों पर फोकसः उनके प्रचार में हॉस्टल, छात्र सुरक्षा और कैंपस की सुविधाओं जैसे अहम मुद्दे रहे। इससे संगठन की राजनीति से अलग मुद्दों पर वोट मांगने में मदद मिली।*

भंडाफोड़ : एफबीआई एजेंट बनकर पोर्न देखने का डर दिखाते थे, सोना-डॉलर में लेते थे रकम

लखनऊ में बैठकर अमेरिकियों से ठगी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सदस्य खुद को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का एजेंट, FDI का अफसर और माइक्रोसॉफ्ट-अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों का मेंबर बताते थे। विदेशी नागरिकों खासकर अमेरिकी लोगों को फोन करके अपने जाल में फंसा लेते थे।

उन्हें ड्रग्स और पोर्नोग्राफी स्कैंडल में शामिल होने की बात बताकर डराते थे। फिर शुरू होता था ठगी का खेल। इसका पैसा, सोना, क्रिप्टो करेंसी और डॉलर में खाते में ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने 16 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया।

>> (शेष पेज 06 पर)

पुलिस के मुताबिक, कॉल सेंटर शिवा उर्फ प्रियांशु कुशवाहा चला रहा था। वह अहमदाबाद का रहने वाला है और फिलहाल फरार है। नेहाल और आशीष कॉल सेंटर चलाने और मैनेजमेंट में प्रमुख भूमिका निभाते थे। दोनों कर्मचारियों की हायरिंग, ट्रेनिंग और उपस्थिति की व्यवस्था देखते थे। गिरफ्तार किए गए लड़के-लड़कियां गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

36 लैपटॉप और 20 मोबाइल बरामद

पुलिस ने मौके से 36 लैपटॉप, 20 मोबाइल, 5 वाई-फाई राउटर, 22 हेडफोन, 20 माउस और 32 लैपटॉप चार्जर बरामद किए हैं। लैपटॉप में डायलर, रिमोट एक्सेस ऐप जैसे अल्ट्रा व्यूअर, सुप्रीमो और फर्जी FBI/FTC जैसी फाइल्स मिली हैं। वहीं, मोबाइल कर्मचारियों के हैं, जो मैनेजर अपने केबिन में जमा करा लेता था।

- पुलिस ने 12 पुरुष और 4 महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, मास्टरमाइंड अब भी फरार है।
- आरोपियों के पास से 36 लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
- पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने में इस्तेमाल की जाने वाली सभी मशीनों को जब्त कर लिया।
- गिफ्ट कार्ड मंगाकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। उसके बाद रकम को मास्टरमाइंड अपने खातों में ट्रांसफर करा लेता था।

'विकसित देशों में भारत से 6 गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन'

पीएम मोदी ने कहा- पर्यावरण की बात करने वाले ही परमाणु ऊर्जा रोकने कोर्ट जाते हैं

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विकसित देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत से करीब 6 गुना ज्यादा है, फिर भी जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी अक्सर विकासशील देशों पर डाल दी जाती है। नई दिल्ली में शनिवार को 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है।

मोदी ने कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, "जो लोग पर्यावरण पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं, जब मैं परमाणु ऊर्जा का काम आगे बढ़ाता हूं तो वे इसे रोकने के लिए अदालतों में जाते हैं।"

पेरिस कॉप-21 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के तहत आयोजित 21वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था।

इसमें करीब 195 देशों ने हिस्सा लिया और पेरिस समझौता अपनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया के औसत तापमान में बढ़ोतरी को 2°C से काफी नीचे रखना और 1.5°C तक सीमित करने की कोशिश करना था।

किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई सम्पन्न

सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन

निर्णय

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक आज एनेक्सी भवन, लखनऊ में अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण सहित बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज,सूचना विभाग,नगर विकास, नमामि गंगे, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। माहवारी प्रारंभ होने से पूर्व किशोरियों को आवश्यक जानकारी एवं तैयारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रदेश में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं और पहलों को समग्र, समन्वित एवं संस्थागत स्वरूप देने के लिए राज्य माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नीति विकसित करने पर कार्य किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित कुमार घोष ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी एवं समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने तथा किशोरियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं और गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें, ताकि किशोरियों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो सकें।

> सुरक्षित एवं स्वच्छ माहवारी व्यवहार को बढ़ावा देने तथा मिथकों, भ्रांतियों और सामाजिक झिझक को दूर करने के लिए डिजिटल, सामाजिक एवं अन्य संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

कक्षा 6 से 12 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्राओं तथा विद्यालय न जाने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों तक भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था विकसित की जाएगी। माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवाओं का लाभ प्रत्येक किशोरी तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें विद्यालय से बाहर रहने वाली किशोरियों और वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा किशोरावस्था संबंधी शिक्षा एवं जागरूकता सत्रों को नियमित शैक्षिक गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा।

सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन

योगी सरकार स्कूलों में नियमित रूप से चलाएगी जागरूकता सत्र

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को अब निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। योगी सरकार इसका दायरा केवल सरकारी विद्यालयों तक सीमित नहीं रखेगी। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ स्कूल छोड़ चुकी और स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों तक निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने की व्यवस्था तैयार की जाएगी।

इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं को एकीकृत करते हुए राज्य स्तरीय नीति विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। किशोरियों के माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए गठित राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की एनेक्सी भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में किशोरियों तक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर मंथन किया गया।

> सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्राओं के साथ स्कूल छोड़ चुकी और स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को भी मिलेगा लाभ

फास्ट न्यूज

वेटनरी फार्मासिस्ट चुनाव संपन्न

लखनऊ। लखनऊ में वेटनरी फार्मासिस्ट संघ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ शाखा का जिला स्तरीय चुनाव 19 सितंबर को संपन्न हुआ। चुनाव में राजकीय पशु चिकित्सालय, मलिहाबाद में तैनात वेटनरी फार्मासिस्ट बृजेश कुमार को जिला महामंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया।

निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण-पत्र में बृजेश कुमार के निर्विरोध निर्वाचन की पुष्टि की गई है।

लखनऊ में रोडवेज एसी बस में लगी भीषण आग

दुबग्गा । लखनऊ में शुक्रवार देर रात रोडवेज की AC बस में आग लग गई। हरदोई-कानपुर रिंग रोड पर उत्कर्ष लॉन के सामने बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद बस में आग लग गई। कुछ ही देर में बस धू-धूकर जलने लगी।

सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि बस के अंदर कोई यात्री या अन्य व्यक्ति नहीं मिला। फायर विभाग के मुताबिक, रात करीब 12:30 बजे चौक फायर स्टेशन को भापतामऊ के पास बस में आग लगने की सूचना मिली थी।

लखनऊ में राष्ट्रीय कर्मचारी रैली घोषणा

लखनऊ। लखनऊ में 19 सितंबर को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय कर्मचारी रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि रैली की तैयारियों के लिए अक्टूबर-नवंबर में देशभर में जनसंपर्क, जागरूकता और कर्मचारी संपर्क अभियान चलाया जाएगा।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की मूलभूत साक्षरता परीक्षा

तमसा संकेत, संवाददाता

- प्रदेश के 5.10 लाख से अधिक 15+ आयु वर्ग के असाक्षर परीक्षा में होंगे शामिल
- मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एवं बीएसए करेंगे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

लखनऊ । भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम मूलभूत साक्षरता परीक्षा का आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदों में 20 सितम्बर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 5.10 लाख असाक्षर प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्रदान कर उन्हें साक्षर बनाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की 75 प्रतिशत तथा पुरुषों की 25 प्रतिशत भागीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 15+ आयु वर्ग के कुल 10.00 लाख असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वित्तीय वर्ष में दो चरणों में, क्रमशः सितम्बर एवं मार्च माह में मूलभूत साक्षरता परीक्षा आयोजित की जानी है। इसी क्रम में प्रथम चरण की परीक्षा 20 सितम्बर को आयोजित होगी।

उल्लास पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 5.10 लाख 15+ आयु वर्ग के असाक्षरों को इस परीक्षा में प्रतिभाग कराया जाएगा।

'अपनी माटी, अपना गांव'-मातृभूमि योजना से गांवों के विकास में जनभागीदारी को नई उड़ान

मातृभूमि के विकास में भागीदारी का सशक्त माध्यम बनी 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना'

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से देश-विदेश में निवास कर रहे ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपनी मातृभूमि एवं गांव के विकास से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो अपने गांव में जनोपयोगी एवं विकासपरक कार्य कराने के इच्छुक हैं।

पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' अपनी माटी, अपने गांव और अपनी जड़ों से जुड़े लोगों को ग्रामीण विकास की प्रक्रिया से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति एवं संस्थाएं, जिनका अपने गांव से भावनात्मक एवं सामाजिक जुड़ाव है, योजना के माध्यम से अपने गांव के विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकते हैं। जनसहभागिता से गांवों में आवश्यक जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण होने के साथ ही ग्रामीणों में अपने गांव के प्रति अपनत्व, जिम्मेदारी और सामुदायिक स्वामित्व की भावना भी मजबूत होगी। उन्होंने सभी इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपनी मातृभूमि के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्रदेश के किसी भी जनपद के किसी गांव में विकास कार्य कराने के लिए सहभागी बन सकती है। इच्छुक दानकर्ता द्वारा परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत अंशदान किया जाता है, जबकि शेष 40 प्रतिशत लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार और समाज की सहभागिता से गांवों में विभिन्न प्रकार के जनोपयोगी विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है।

> मातृभूमि योजना में दानकर्ता की सहभागिता को विशेष सम्मान भी प्रदान किया जाता है। शासनादेश के अन्तर्गत दानकर्ता के प्रस्ताव के अनुरूप निर्मित परियोजना पर शिलापट्ट लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे दानकर्ता की विकास कार्य में सहभागिता को स्थायी रूप से सम्मानित करने के साथ-साथ अन्य लोगों को भी अपने गांव के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

देश-विदेश में बसे लोगों को अपनी मातृभूमि के विकास से जोड़ रही 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' अपनी जड़ों से जुड़कर गांवों के विकास में सहभागी बनें-मातृभूमि योजना दे रही जनभागीदारी को नया आयाम

समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा

पंचायती राज निदेशक श्री अमित कुमार सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य गांव से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं को स्थानीय विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि योजना जनसहभागिता को ग्रामीण विकास से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है, जिसके अंतर्गत दानदाताओं की इच्छानुसार जनोपयोगी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे गांवों में आवश्यक सुविधाओं के विकास को गति मिलने के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने 12.750 किलो गांजा, 3 फोन बरामद किए, गोंडा से लाते थे खेप

सफारी से गांजा सप्लाई कर रहे 2 तस्कर गिरफ्तार

तमसा संकेत, एजेंसी

मोहनलालगंज (लखनऊ)। लग्जरी सफारी में गांजे की बड़ी खेप लेकर लखनऊ में सप्लाई करने निकले दो युवकों को नगराम पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सफारी की तलाशी ली तो बोरी में 12.750 किलो गांजा मिला। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए है। आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन, पीली धातु की चेन और 3,100 रुपए भी मिले। वाहन समेत कुल बरामदगी की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है।

डीसीपी साउथ मो. मुश्ताक ने बताया कि,17 सितंबर को नगराम-गंगागंज मार्ग पर शिवपुरा मोड़ के पास चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान काले रंग की टाटा सफारी संख्या UP32EL8000 को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी में सवार युवकों की पहचान सचिन सिंह (32) निवासी करूआ देवरा, बाराबंकी, हाल पता रामबक्शखेड़ा, गोसाईगंज और सत्यम सिंह (20) निवासी तमोरिया, नगराम के रूप में हुई। ये लोग गोंडा से गांजा लाकर यहां बेचते थे। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सचिन ने बताया कि गांजा तस्करी से मिले पैसों से उसने मोबाइल फोन, पीली धातु की चेन और सफारी गाड़ी खरीदी थी। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और गांजे की सप्लाई के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है।

लखनऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गैंग लखनऊ और आसपास के जिलों में गांजे की सप्लाई करता है। पुलिस के अनुसार, गांजे की खेप गोंडा के जरवल और आसपास के इलाकों से गैंग के दूसरे सदस्यों के जरिए उपलब्ध कराई जाती थी। इसके बाद 10 से 15 किलो गांजा सफारी में छिपाकर लखनऊ लाया जाता था। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि लखनऊ पहुंचने के बाद गांजे को करीब दो-दो किलो की खेप में अलग-अलग सदस्यों को दिया जाता था। इसके बाद छोटी पुड़िया बनाकर आसपास के इलाकों में बिक्री की जाती थी।

बिल्लियों को बोरे में भरकर फेंका लंगूर को खंभे से बांधा

एनजीओ ने किया रेस्क्यू, मुकदमा दर्ज करने की मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ में शुक्रवार को महानगर स्थित शालीमार गैलेंट में पशु क्रूरता और वन्यजीव को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिसर में कुछ बिल्लियों को बोरों में भरकर बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही थी, जबकि एक लंगूर को रस्सी से बांधकर रखा गया था।

सूचना मिलने पर पशु संरक्षण संस्था 'आसरा-द हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट' (AASRA) की टीम ने वन विभाग और डायल-112 पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचकर बिल्लियों और लंगूर को रेस्क्यू कराया।

संस्था की संचालक चारु खरे की ओर से महानगर थाने में लिखित शिकायत देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के मुताबिक, बिल्लियों को जान से मारकर बाहर फेंकने के उद्देश्य से बोरों में बंद किया गया था। सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर बोरों में बंद बिल्लियों को बाहर निकाला। साथ ही परिसर में रस्सी से बंधे लंगूर को भी मुक्त कराया गया। संस्था ने शिकायत में आरोप लगाया है कि परिसर में लंगूर को शाहरुख नाम के व्यक्ति ने बंधक बनाकर रखा था। संस्था ने शालीमार गैलेंट के प्रेसिडेंट विकास टंडन और सेक्रेटरी सुमित गुप्ता की भूमिका की भी जांच की मांग की है। संस्था का कहना है कि इतने बड़े रिहायशी परिसर में वन्यजीव को किसकी जानकारी या अनुमति से रखा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। AASRA ने पुलिस से शालीमार गैलेंट परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज तत्काल सुरक्षित कर कब्जे में लेने की मांग की है। संस्था का कहना है कि फुटेज मामले में महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य साबित हो सकती है और समय बीतने पर इसके ओवरराइट होने की आशंका है।

लखनऊ डीएम से तहसीलदार और लेखपालों की शिकायत

आरोप- ब्लॉक के अधिकारी लापरवाह, कई गांवों में सुलभ शौचालय नहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

सरोजनी नगर, लखनऊ। लखनऊ की सरोजनीनगर तहसील में शनिवार को समाधान दिवस पर तहसीलदार और लेखपालों की शिकायत कर दी गई। जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर तहसील में पहुंचे हुए थे। वकीलों ने उनसे कहा कि तहसीलदार उनसे और आम लोगों से गलत भाषा बोलते हैं। इसके अलावा कई लेखपाल अपने घर से दफ्तर चला रहे हैं। वो तहसील नहीं आते। इसके अलावा डीएम के सामने भाजपा के लखनऊ जिला मंत्री संजीव कुमार मिश्रा कई महिलाओं के साथ पहुंच गए। उन्होंने शिकायत की कि सरोजनीनगर ब्लॉक के अधिकारी लापरवाह हैं। अधिकारियों की वजह से ही कई गांवों में आज तक सुलभ शौचालय नहीं बने। महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। गांवों में पानी की सप्लाई और गोशालाओं में चारा की कमी है।

तहसील परिसर में नए बने कोर्ट के लिए कम से कम दो और कमरे बनाने की मांग की गई। परिसर के सामने नाला बनाने और केस लड़ने वालों के बैठने के लिए बेंच लगाने की भी मांग हुई। वकीलों ने खराब वाटर कूलर और सोलर लाइटों को ठीक कराने की मांग रखी।

वकील बोले- तहसीलदार का ट्रांसफर किया जाए

बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेश प्रताप सिंह और महामंत्री राजेंद्र यादव की अगुवाई में वकील तहसील दिवस में पहुंचे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार फोन नहीं उठाते हैं। गलत भाषा बोलते हैं। उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। कई लेखपाल अपने घर से दफ्तर चला रहे हैं। अवैध वसूली के लिए अपना सहायक भी रखे हुए हैं। 1 साल से तैनात ऐसे सभी लेखपालों को हटाया जाए। जिलाधिकारी ने तहसीलदार और लेखपालों पर लगे आरोपों की जांच कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

मॉर्निंग वॉक पर निकले छात्र को डंपर ने रौंदा, मौत

मलिहाबाद, लखनऊ। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले 11वीं के छात्र आरिफ (20) को एक अज्ञात डंपर ने रौंद दिया। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस डंपर की तलाश कर रही है। यह घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे लखनऊ-हरदोई राजमार्ग पर मुजासा सुपर नर्सरी के पास हुई। आरिफ अपने घर बड़ी गढ़ी, मलिहाबाद लौट रहा था, तभी हरदोई की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से आरिफ का मोबाइल फोन बरामद किया और उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी। आरिफ सफा पब्लिक स्कूल मलिहाबाद में 11वीं का छात्र था और नीट की तैयारी भी कर रहा था। वह स्कूल के बाद अपने पिता हनीफ के साथ खेती में भी मदद करता था।

तबादला: प्रेग्नेंट चारु निगम को पीएसी गाजियाबाद भेजा गया, चारु निगम इस समय प्रेग्नेंट

यूपी में 35 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। योगी सरकार ने 35 IPS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। शाम 6 बजे लिस्ट जारी कर दी गई। इनमें से अधिकतर ऐसे अफसर हैं, जो तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात रहे हैं।

यूपी 112 की SP चारू निगम का एक महीने के भीतर दूसरी बार ट्रांसफर हुआ है। उन्हें गाजियाबाद 47वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है। पहले भी IPS चारू इस कंपनी में सेनानायक रह चुकी हैं। चारू निगम इस समय प्रेग्नेंट हैं। यूपी 112 में तैनाती से पहले सुल्तानपुर SP थीं। जब उन्हें वहां से हटाया गया तो X पोस्ट के जरिए दर्द बयां किया था। उन्होंने लिखा,

सुल्तानपुर से विदाई लेते हुए मैं यह बात साफ करना चाहती हूं कि मां बनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। प्रेग्नेंसी के बावजूद सुल्तानपुर में बिताए अपने 197 दिनों के कार्यकाल के दौरान मैं जिले की जिम्मेदारी पूरी क्षमता के साथ संभालने में सक्षम थी। 2013 बैच की IPS चारू निगम का तबादला 20 अगस्त को यूपी 112 में किया गया था। सुल्तानपुर में उनके 6 महीने के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर हुई पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और भाजपा एमएलसी देवेंद्र सिंह के साथ विवाद काफी सुर्खियों में रहा था।

श्रुति श्रीवास्तवः अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) वाराणसी रहीं श्रुति श्रीवास्तव को प्रयागराज का ADCP बनाया गया है।

प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रुति ने काशी आने पर अभिनेत्री रवीना टंडन का इंटरव्यू किया था।

विक्रम दहियाः ASP पीलीभीत से ASP चंदौली बनाए गए हैं। हरियाणा में करनाल के रहने वाले विक्रम दहिया ने एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया और इसके बाद आईआईएम रोहतक से एमबीए की डिग्री हासिल की। 'लावा इंटरनेशनल' कंपनी में करीब 37 लाख के सालाना पैकेज पर रीजनल/जोनल सेल्स मैनेजर के रूप में भी काम किया था।

साइबर अपराध के 103 मुकदमे दर्ज

57 आरोपियों पर कार्रवाई, पीड़ितों के 60 लाख रुपए वापस कराए गए

धोखाधड़ी

तमसा संकेत, एजेंसी

एसएसपी ने बताया कि साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए साइबर थाना और जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। इनके जरिए साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध लेनदेन के लिए इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल खातों' के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में दर्ज तीन मुकदमों में 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भेजा गया है। वहीं, एक आरोपी को जेल भेजा गया है।

उन्नाव। उन्नाव में साइबर अपराध के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने शनिवार को बताया कि 1 जनवरी 2026 से अब तक साइबर अपराध से जुड़े 103 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें 57 मामले सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के हैं, जबकि 46 मामले वित्तीय धोखाधड़ी के हैं। पुलिस ने इन मामलों में 57 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कुल 2 करोड़ 54 लाख रुपए की ठगी हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 92 लाख रुपए होल्ड कराए, जबकि 60 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए। पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले 1210 मोबाइल फोन को बंद कराया है। इसके अलावा 347 मोबाइल फोन के IMEI नंबर स्थायी रूप से बंद कराए गए हैं। एसएसपी के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से अब तक NCRP पोर्टल पर वित्तीय अपराध से जुड़े 3202 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें करीब 2 करोड़ 93 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं। साइबर अपराध से बचाव के लिए पुलिस हर सप्ताह और हर महीने जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिसकर्मियों को भी साइबर अपराध की रोकथाम और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल-कॉलेजों और अन्य स्थानों पर जाकर लोगों को साइबर ठगी के अलग-अलग तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि साइबर ठग कई बार पुलिस या अन्य अधिकारियों की वर्दी और पहचान का दुरुपयोग कर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा सके।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से रहें सावधान

एसएसपी ने लोगों से अपील की कि मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक को न खोलें और किसी के साथ OTP शेयर न करें। उन्होंने 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर होने वाली ठगी से भी सावधान रहने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी व्यक्ति को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार नहीं करती है। गिरफ्तारी की कार्रवाई भौतिक रूप से की जाती है और व्यक्ति को थाने लाया जाता है। एसएसपी ने बताया कि साइबर ठग कई बार पुलिस या अन्य अधिकारियों की वर्दी और पहचान का दुरुपयोग कर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा सके।

गंगा का जलस्तर घटा, बाढ़ प्रभावितों को परेशानी

कई इलाकों में घरों के सामने अब भी घुटनों तक भरा है पानी, नाव से हो रही आवाजाही

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही गंगा के कारण पश्चिमी गंगाघाट समेत कई इलाकों में अब भी घरों के सामने घुटने से लेकर कमर तक पानी भरा है। रास्तों पर पानी होने से लोगों को जरूरी कामों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जलस्तर में लगातार गिरावट से लोगों को राहत की उम्मीद जगी है, लेकिन बस्तियों से पानी निकलने और जनजीवन सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। 30% आबादी बाढ़ की चपेट में आई थी सितंबर की शुरुआत में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 113 मीटर को पार कर 113.120 मीटर के इस साल के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था। अचानक बढ़े जलस्तर के कारण गंगाघाट नगर क्षेत्र की करीब 30 प्रतिशत आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। पश्चिमी गंगाघाट के कर्बला, गोतखोर, हुसैन नगर और तेजीपुरवा समेत कई मोहल्लों में पानी भर गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में फत्तेखेड़ा, गगनीखेड़ा, लक्ष्मीखेड़ा, बालघाट चौकी क्षेत्र, श्रीनगर, मालवीय नगर, मनोहर नगर, गंगा नगर, शक्तिनगर, पोनी गांव, पीपरखेड़ा, गजियाखेड़ा और झब्बूपुरवा समेत कई इलाकों में भी बाढ़ का असर रहा। गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी बाढ़ प्रभावित बस्तियों में पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई घरों के सामने अब भी घुटनों से लेकर कमर तक पानी है। गलियों और रास्तों में पानी होने के कारण पैदल निकलना मुश्किल है। ऐसे में लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। घरों में जरूरी सामान पहुंचाने और रोजमर्रा के कामों के लिए भी लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अब भी ठप है। उमस भरी गर्मी में लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। मोबाइल फोन चार्ज नहीं होने के कारण लोग रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है।

फास्ट न्यूज

हरदोई में पावर हाउस का घेराव

हरदोई। हरदोई के पिहानी में राभा फीडर की बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर किसान यूनियन ने पिहानी पावर हाउस का घेराव कर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया।

किसान नेता राम प्रकाश मौर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने पावर हाउस परप्रदर्शन किया।

किसानों का कहना है कि लगभग 20 दिन से राभा फीडर में बिजली नहीं आ रही है, जिससे उनकी फसलें सूख रही हैं।

मिशन शक्ति कार्यशाला में छात्राओं ने किया नुक्कड़ नाटक

उन्नाव। उन्नाव में डॉ. जी. नाथ इंटर कॉलेज में 'मिशन शक्ति' के तहत महिला सुरक्षा और जागरूकता पर एक कार्यशाला हुई।

शनिवार दोपहर करीब दो बजे हुई इस कार्यशाला में छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और कई हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी नगर विनी सिंह ने की। इस दौरान छात्राओं ने 'मिशन शक्ति' पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक पेश किया। हालात में हिम्मत से काम लेने का संदेश दिया।

शराब के ठेके पर जाली नोट चलाने पहुंचे दो युवक

हरदोई। हरदोई जनपद के शाहाबाद कस्बे में मौलागंज बस स्टैंड स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर शनिवार को दो युवक एक ही सीरीज के जाली नोट लेकर शराब खरीदने पहुंचे। सतर्क सेल्समैन की सूझबूझ से नकली नोटों का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मामला शुक्रवार रात करीब 8 बजे का है। आरोपियों ने दो नोट 200 के और एक नोट 100 रुपये का नोट दिया था।

पत्नी की नाक काटने के मामले में पति,सास-ससुर पर एफआईआर

हरदोई में पति के गुप्तांग को दांत से काटने का आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई में शुक्रवार को मछली बनाने से मना करने पर पति-पत्नी में विवाद हुआ था। शनिवार को विवाहिता की नाक काटने के मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

घटना में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पत्नी पर पति के गुप्तांग में चोट पहुंचाने, जबकि पति पर मारपीट कर पत्नी की नाक काटने का आरोप है।

घायल विवाहिता का हरदोई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस टीम साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

मामला सांडी थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे का है। सांडी थाना क्षेत्र के मुंशीगंज निवासी दीपक की शादी करीब 10 साल पहले सुरसा थाना क्षेत्र के ढोलिया गांव निवासी साधना से हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते साधना करीब छह महीने पहले मायके चली गई थी। पुलिस के अनुसार, इस दौरान वह कुछ समय अपने चचेरे देवर के साथ भी रही थी।

एएसपी पूर्वी सुबोध गौतम के मुताबिक, पति से विवाद और प्रेम-प्रसंग के चलते विवाहिता अपने चचेरे देवर के साथ चली गई थी।

गुरुवार को वह अचानक ससुराल पहुंची।

इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया।

2 जगह अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

बरौला जाफराबाद और बीमा नगर में एडीए की कार्रवाई, बिना नक्शा हुआ था निर्माण

तमसा संकेत, एजेंसी

अलीगढ़। अलीगढ़ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कुलदीप मीना के निर्देश पर जोन-4 की टीम ने बन्नादेवी थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करने वालों में खलबली मच गई। ADA के अनुसार, दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। सुनवाई के बाद दोनों स्थलों के संबंध में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए थे। इन्हीं आदेशों के अनुपालन में 19 सितंबर को प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया। पहली कार्रवाई ग्राम बरौला जाफराबाद में प्राइमरी स्कूल के पास की गई।

यहां गाटा संख्या 219 (भाग) में अवैध तरीके से प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी।

प्राधिकरण के मुताबिक स्थल प्रेमपाल पुत्र मदन मोहन, हर प्रसाद पुत्र ठाकुर दास और शंकर लाल पुत्र हरी सिंह के नाम दर्ज है। यह क्षेत्र तहसील कोल और थाना बन्नादेवी के अंतर्गत आता है। टीम ने मौके पर पहुंचकर विकसित किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग कार्य को ध्वस्त कराया।

बीमा नगर में भी अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

दूसरी कार्रवाई बन्नादेवी थाना क्षेत्र के बीमा नगर, सारसौल जीटी रोड पर की गई। यहां बंटी सिंह के स्थल पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। ADA की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण और प्लॉटिंग से जुड़े अवैध विकास कार्य को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी रही, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

प्लॉट खरीदने से पहले नक्शा जांचने की अपील

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या जमीन को खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी का नक्शा और लेआउट प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं, इसकी जांच जरूर करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अलीगढ़ विकास क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने या निर्माण कराने से पहले निर्धारित अनुमति लेना और भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत कराना जरूरी है। ADA की टीम अवैध प्लॉटिंग और विकास कार्यों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

बरौला जाफराबाद में स्कूल के पास हो रही थी प्लॉटिंग

पहली कार्रवाई ग्राम बरौला जाफराबाद में प्राइमरी स्कूल के पास की गई। यहां गाटा संख्या 219 (भाग) में अवैध तरीके से प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण के मुताबिक स्थल प्रेमपाल पुत्र मदन मोहन, हर प्रसाद पुत्र ठाकुर दास और शंकर लाल पुत्र हरी सिंह के नाम दर्ज है। यह क्षेत्र तहसील कोल और थाना बन्नादेवी के अंतर्गत आता है। टीम ने मौके पर पहुंचकर विकसित किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग कार्य को ध्वस्त कराया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अलीगढ़ विकास क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उन्नाव में मंदिर में खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना

वैदिक विधि-विधान से हुई प्राण प्रतिष्ठा, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के शांति नगर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार दोपहर नई मूर्तियों की पुनर्स्थापना की गई। शुक्रवार रात मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। दोपहर करीब तीन बजे वैदिक विधि-विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ और नंदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात एक युवक ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया था। आसपास के लोगों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया था। भाजपा नेता बिमल द्विवेदी मौके पर पहुंचे और शहर कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद शहर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद खंडित मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित करने का फैसला लिया गया। शनिवार को बिमल द्विवेदी के नेतृत्व में और मंदिर के संरक्षक सुरेश वर्मा की देखरेख में भगवान भोलेनाथ और नंदी जी की नई मूर्तियां स्थापित कराई गईं। आचार्य श्रवण कुमार वाजपेयी, आचार्य वासु जी और आचार्य मनोज अवस्थी ने पूरे वैदिक विधि-विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर जलाभिषेक किया और सुख-शांति की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल रहा। इस अवसर पर जिला प्रभारी अजय त्रिवेदी, नवीन वर्मा, शक्ति वर्मा, उमेश सिंह पंकज, अश्विनी पांडेय, पीयान अवस्थी, आदित्य, विकास सविता, अंकुर त्रिपाठी, अमोली वाजपेयी समेत बड़ी संख्या में शिवभक्त उपस्थित रहे।

समाधान दिवस में पहुंचीं 201 शिकायतें

19 का मौके पर निस्तारण, राजस्व की 56 शिकायतें सबसे ज्यादा

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के सफीपुर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस लगा। इसमें जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने लोगों की शिकायतें सुनीं। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह भी वहां मौजूद थे। राजस्व, पुलिस, विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, बिजली और सप्लाई समेत कई विभागों से जुड़ी कुल 201 शिकायतें मिलीं। इनमें से 19 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। बाकी मामलों को समय पर और अच्छे से निपटाने के लिए अधिकारियों को कहा गया। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से देखा जाए और उसका निष्पक्ष और सही समाधान किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायत जिस तरह की हो, उसका समाधान भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। समाधान दिवस में डीएम ने दिए सख्त निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं।

दूसरे विभागों से जुड़ी 29 शिकायतें दर्ज की गईं। समाधान दिवस के दौरान डीएम ने सेवा संकल्प अभियान के तहत दैवीय आपदा से पीड़ित एक व्यक्ति को चार लाख रुपये का चेक दिया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना और कृषक दुर्घटना योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिए गए। डीएम ने तहसील परिसर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टालों का भी देखा।

समाधान दिवस में सबसे ज्यादा 56 शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी थीं। डीएम ने जमीन विवाद, पैमाइश (नाप-जोख), अवैध कब्जे और दूसरे गंभीर राजस्व मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस से जुड़ी 41, विकास विभाग की 29, समाज कल्याण की 13, बिजली की 16, सप्लाई की 13 और शिक्षा विभाग की 4 शिकायतें भी मिलीं।

सुविधाओं के बारे में जानकारी

उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और लाभार्थियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सफीपुर फाल्गुनी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, जिला विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी समेत कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे।

कोशिश : उन्नाव में बेहोश होते ही सांसें रुकने लगी थीं, अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान

सिपाही ने सीपीआर देकर होमगार्ड की जान बचाई

- यातायात ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
- हेड कॉन्सटेबल दिनेश कुमार ने बिना समय गंवाए सीपीआर देना शुरू किया।

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में यातायात ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द के बाद वह यातायात कार्यालय में बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी सांसें भी रुकने लगीं। मौके पर मौजूद हेड कॉन्सटेबल दिनेश कुमार ने बिना समय गंवाए सीपीआर देना शुरू किया। कुछ देर की कोशिश के बाद होमगार्ड की सांसें वापस आने लगीं। शनिवार को घटना का वीडियो सामने आया, जिसके बाद एसपी ने मुख्य आरक्षी की तत्परता की सराहना की। होमगार्ड अमित कुमार चौराहे पर यातायात संभाल रहे थे। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। इसके साथ उलझन और बेचैनी भी होने लगी। हालत बिगड़ने पर वह पास स्थित यातायात कार्यालय पहुंचे। वह अपनी परेशानी बता पाते, इससे पहले ही उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। अमित कुमार को जमीन पर गिरा देखकर कार्यालय में मौजूद मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने साथी कर्मचारियों से होमगार्ड के जूते उतारकर हाथ-पैर रगड़ने को कहा। इसके बाद खुद सीपीआर देना शुरू कर दिया।

यातायात निरीक्षक के साथ जिला अस्पताल ले गए, इलाज जारी

होमगार्ड की हालत में सुधार होने के बाद यातायात निरीक्षक सुनील कुमार और मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया। ईएमओ डॉ. आशीष सक्सेना ने बताया कि होमगार्ड का उपचार चल रहा है और उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।

वीडियो सामने आने पर एसपी ने मुख्य आरक्षी की तारीफ की

घटना के अगले दिन सामने आए वीडियो में मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार होमगार्ड को लगातार सीपीआर देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में उनकी तत्परता की चर्चा हुई। एसपी ने भी दिनेश कुमार की सजगता और समय पर किए गए प्रयास की सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी आपात स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार मिलने से मरीज को अस्पताल पहुंचने तक संभालने में मदद मिल सकती है।

जिला अस्पताल में नवजात के परिजनों में मारपीट

इलाज के दौरान शुरू हुआ विवाद, कहासुनी के बाद हाथापाई

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव जिला अस्पताल में नवजात बच्चे के इलाज के दौरान उसके परिजनों के बीच विवाद हो गया। शुक्रवार को कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा हुआ। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बच्चे की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया था। सदर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह निवासी नवजात की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इसी बीच अस्पताल में मौजूद बच्चे के परिजनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को अलग कराने की कोशिश की।

इसी दौरान किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया। शनिवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद घटना चर्चा में आ गई। फिलहाल नवजात का इलाज कानपुर हैलट में चलने की जानकारी सामने आई है। बच्चे को जहरीला पदार्थ दिए जाने के आरोप की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वहीं, अस्पताल में मारपीट को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस में शिकायत और जांच के बाद ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

सम्पादकीय

मुश्किलों से घिरीं ममता

ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले निर्वाचन आयोग ने अंतरिम फैसले के जरिये उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न जब्त कर लिया और अब राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में से एक में उनकी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। इससे यही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों तक शासन करने वालीं ममता बनर्जी सत्ता हाथ से जाते ही चौतरफा मुश्किलों से घिर गई हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में पराजय के बावजूद तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी, लेकिन फिर बिखराव का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के अधिसंख्य विधायकों ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और फिर बीस लोकसभा सदस्य भी पार्टी से छिटक गए। आज स्थिति यह है कि ममता बनर्जी विधानसभा में भी अपना प्रभाव खो चुकी हैं और लोकसभा में भी। यह भी ध्यान रहे कि उनके कुछ राज्यसभा सदस्य भी पार्टी छोड़ चुके हैं।

यह संभवतः पहली बार है, जब किसी राज्य में लगातार तीन कार्यकाल पूरे करने वाली कोई पार्टी इस तरह बिखरी हो। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय ममता बनर्जी जिस तरह चौतरफा संकट से घिरी हुई हैं, उसे देखते हुए यह कहना कठिन है कि राजनीतिक रूप से उनकी वापसी हो सकती है। वैसे तो जैसे तृणमूल कांग्रेस में टूट-फूट हुई, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों दलों के मुकाबले ममता की पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सशक्त थी। ममता चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगी, लेकिन इसमें संदेह है कि उन्हें राहत मिल सकेगी।

तृणमूल कांग्रेस की दुर्गति यही बता रही है कि विचारधारा-विहीन राजनीतिक दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं होता और जैसे ही वे सत्ता खोते हैं अथवा सत्ता पाने में सक्षम नहीं दिखने लगते, उनमें बिखराव शुरू हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस में बिखराव का मूल कारण यह है कि परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आईं ममता बनर्जी ने मनमाने तरीके से शासन चलाया। उन्होंने भ्रष्ट और अराजक तत्वों को संरक्षण प्रदान किया। इससे ऊबी जनता ने मौका मिलते ही उन्हें सबक सिखाया। ऐसा ही वामदलों के साथ हुआ था। दोनों में साझा यह है कि उन्होंने दमनात्मक तरीके से शासन चलाया। भले ही ममता बनर्जी अपनी पार्टी की दुर्गति के लिए भाजपा और चुनाव आयोग को दोष दें, लेकिन अपनी स्थिति के लिए वही जिम्मेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस की दुर्गति से सत्ता में आकर मनमानी करने वाले राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए।

सत्ता से संघर्ष तक: ममता बनर्जी का राजनीतिक यथार्थ

> तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक विभाजन के बाद दोनों गुटों द्वारा अधिकार जताए जाने के कारण आयोग को कड़ा कदम उठाना पड़ा। वर्षों पूर्व जिस पहचान को उन्होंने अपने कड़े परिश्रम और संघर्ष से सींचा था, उसी से वंचित हो जाना उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संवैधानिक झटका माना जा रहा है।

ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर एक छात्र राजनीति की साहसी नायिका से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने और वर्तमान समय में घोर राजनीतिक व कानूनी संकटों से घिरने तक की एक बड़ी दास्तान है। जो 'दीदी' कभी सड़कों पर वामपंथ के 34 साल के किले को ढहाने के लिए जानी जाती थीं, वे आज अपनी राजनीतिक यात्रा के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ममता बनर्जी पर मुश्किलों के पहाड़ टूटने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं- पहला, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में लगा, जहाँ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हार का सामना करना पड़ा और राज्य में भाजपा की सरकार बनी। खुद ममता बनर्जी को भी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी।

15 साल तक राज्य पर राज करने के बाद सत्ता से बाहर होना उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा, ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत हमेशा उनकी पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ थी। लेकिन वर्तमान में टीएमसी के भीतर एक बड़ी बगावत छिड़ गई है। कई विधायकों और सांसदों ने अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और पार्टी में तानाशाही रवैये को लेकर बगावती रुख अख्तियार कर लिया है, जिससे पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है। तीसरा, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा कानूनी और भावनात्मक झटका तब लगा जब चुनाव आयोग ने पार्टी में आंतरिक विवाद के कारण तृणमूल कांग्रेस के नाम और उनके प्रसिद्ध चुनाव चिह्न 'जोड़ा फूल' को फ्रीज (रोक लगा दी) कर दिया। आयोग ने दोनों गुटों को अस्थाई रूप से नए नाम और सिंबल दिए हैं। ममता बनर्जी ने इसे भारतीय लोकतंत्र का 'काला दिन' बताया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चौथा, सत्ता से हटते ही ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है- चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और सांप्रदायिक बयान देने के आरोप में उनके खिलाफ कोलकाता और सिलीगुड़ी में एफआई-आर दर्ज की गई हैं। अगस्त 2026 में कोलकाता में छात्र संगठन (टीएमसीपी) की रैली के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में भी पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया है। उनकी पिछली सरकार पर एक विज्ञापन एजेंसी को रु. 635 करोड़ से अधिक का टेंडर देने में गड़बड़ी जैसे भ्रष्टाचार के नए आरोप लग रहे हैं। पांचवां, ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को जनता की लड़ाई लड़ने वाली और महिलाओं के अधिकारों की रक्षक के रूप में पेश किया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर उनके विवादित बयानों और भ्रष्टाचार के मामलों (जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला आदि) ने उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। जनता में पैदा हुए इसी आक्रोश और सत्ता-विरोधी लहर ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। संघर्ष की नायिका का वर्तमान रुख, इन सब मुश्किलों के बावजूद, 17 साल की उम्र में दूध के बूथ और स्टेनोग्राफर का काम करके अपने परिवार को संभालने वाली ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे राजनीतिक संन्यास नहीं लेंगी और वे इस 'गंदे खेल' के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई जारी रखेंगी। आगामी उपचुनावों के लिए उन्होंने रणनीति बदलते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा भी की है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ममता बनर्जी का नाम एक ऐसी जननेता के रूप में दर्ज रहा है, जिन्होंने शून्य से उठकर जन आंदोलनों के बल पर दशकों पुरानी राजनीतिक संरचनाओं को हिला दिया। छात्र राजनीति के समय से ही उनकी पहचान एक बेबाक और निर्भीक व्यक्तित्व के रूप में रही है। तीन दशकों से अधिक लंबे वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने वाली दीदी ने पूरे पंद्रह वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एकछत्र राज किया। परंतु समय का चक्र ऐसा घूमा है कि वही जुझारू नेत्री आज अपनी ही राजनीतिक यात्रा के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में मिली पराजय, दल के भीतर भड़की बगावत, चौतरफा वैधानिक कार्यवाहियों का शिकंजा और दल की मूल पहचान यानी नाम तथा चुनाव चिह्न का छिन जाना, इन सबने मिलकर उनके समक्ष अस्तित्व रक्षा की अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी है। हाल के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में सामने आए। पंद्रह वर्षों के निरंतर शासन के बाद तृणमूल कांग्रेस को जन-असंतोष और प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों में न केवल उनकी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी, बल्कि ममता बनर्जी को स्वयं अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से पराजय का स्वाद चखना पड़ा। इस परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य में बदलाव की लहर अत्यधिक तीव्र थी। निरंतर शासन से उपजी असंतुष्टि, विभिन्न भर्ती घोटालों के आरोप तथा स्थानीय स्तर पर उपजे जन-रोष ने मिलकर उनकी दलगत जड़ों को कमजोर कर दिया, जिससे राज्य में एक नए राजनीतिक समीकरण का उदय हुआ। किसी भी क्षेत्रीय दल की वास्तविक शक्ति उसका सुदृढ़ संगठन, शालीन भाषा, लोकतांत्रिक मर्यादा और नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा होती है। तृणमूल कांग्रेस में लगभग तीन दशकों तक ममता बनर्जी ही सर्वमान्य चेहरा और अंतिम निर्णयकर्ता रहीं। किंतु चुनावी असफलता के उपरांत पार्टी के भीतर दबा हुआ असंतोष अचानक बाहर आ गया। विधायकों और सांसदों के एक बड़े धड़े ने शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए।

यद्यपि उन्होंने इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताते हुए शीर्ष अदालत का द्वार खटखटाया है, परंतु तत्काल रूप से इस स्थिति ने दल के कार्यकर्ताओं में भारी असमंजस पैदा कर दिया है। सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी बहुआयामी कानूनी चुनौतियों से भी घिर गई हैं।

- ललित गर्ग

स्टेट बैंक ने पिछले ...

हरीश कुमार सिंह

यूपीआई भुगतान पर टैक्स अव्यावहारिक लागू न करना ही समाधान

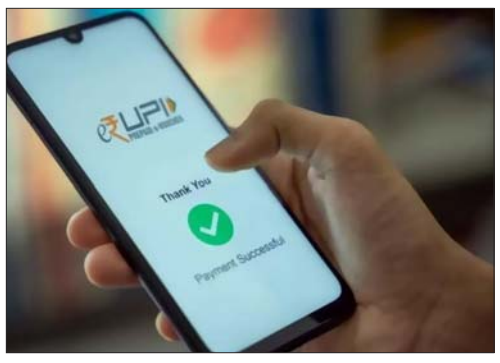

पिछले दस वर्षों से मुफ्त में यूपीआई से भुगतान करने की आदत हम सबको हो गई थी। चाय वाले से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक, एक क्यूआर से देश में लेनदेन आसानी से चल रहा था। और अब अचानक से खबर आई कि दो हजार रुपये से ज्यादा के मोबाइल से भुगतान करने पर टैक्स लगेगा। सरकार का कहना है कि भुगतान जिस व्यापारी को किया गया है उससे टैक्स वसूला जाएगा। प्रचार किया जा रहा है कि टैक्स आम आदमी से नहीं लिया जाएगा बल्कि सामने वाला व्यापारी भरेगा। ये कौन सा तर्क है? सामने वाला व्यापारी क्या इस देश का नहीं है? वह भी तो देश का ही नागरिक है। क्या उसकी जेब काटना देशभक्ति हो गया? और व्यापारी को जो टैक्स देना है, उसका नाम भी कितना छलावा भरा है - एमडीआर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट।

अब इसमें डिस्काउंट अर्थात कटौती क्या है? नाम डिस्काउंट है और वसूल रहे हैं टैक्स। वैसे ही जैसे हर बार आदमी की जेब काटने से पहले नए शब्दों को गढ़ा जाता है। जैसे देश भर में आम आदमी के टैक्स से बनने वाली सड़क पर जबरन के टोल नाकों पर भी टोल टैक्स का नाम यूजर फी है, महंगाई का नया नाम विकास है और अब यूपीआई पर वसूलने वाला टैक्स, डिस्काउंट अर्थात कटौती हो गया है। आदेश जारी हो गया है जो आगामी पंद्रह अक्तूबर से प्रभावशील है और दो हजार रूपये तक के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा मगर दो हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत अधिकतम तीन सौ रुपये टैक्स व्यापारी से लिया जायेगा जिसको ग्राहक ने भुगतान किया है। डिजिटल भुगतान तो देश में आने और छा जाने वाली क्रांति थी तो क्रांति पर टैक्स कब से लगने लगा मित्रों । सरकार और कॉर्पोरेट जियो कंपनी में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। पहले आदत डालो, नशे जैसी, अफीम जैसी और फिर कीमत वसूल करना चालू कर दो। जब जियो क्रांति आई तो कई महीनों तक जियो ने मुफ्त का डाटा और गजब की स्पीड दी और पूरा इंडिया सिर्फ जियो का दीवाना हो गया। बाकी टेलीकॉम कंपनियां लगभग बंद हो गयी तो कुछ ने एकीकरण कर लिया। फिर जब जियो का एकाधिकार हो गया तो फिर जियो ने रंग दिखाया और डाटा की कीमत वसूलना आरम्भ कर दी। आज सबसे ज्यादा महंगा डाटा जियो का है पर मजबूरी है कि अब और कोई कंपनी टक्कर में नहीं है। घर घर डिलीवरी करने वाली कंपनियों का भी यही मॉडल रहा है। सरकार ने भी यही किया। वर्ष 2020 में खुद ही जीरो शुल्क किया था ताकि लोग डिजिटल अपनाएं। अब जब एक सेकंड में सात हजार से ज्यादा मोबाइल से भुगतान होने लगे और सबको लत सी लग गई तो ले आये टैक्स।मीडिया की भी जितनी तारीफ की जाये, कम है। प्रचार कर रहा है कि सिर्फ चार-पांच प्रतिशत को ही टैक्स लगेगा, बाकी छियानवे प्रतिशत मुक्त रहेंगे। अरे ये बाकी छियानवे ही तो इन चार को भुगतान करेंगे तो टैक्स तो खूब मिलेगा न। और जब छियानवे प्रतिशत से नहीं ले रहे तो इन चार को भी छोड़ दीजिये न। काहे देश भर में हल्ला मचवा रहे। भारत में कौन सा व्यापारी अपनी जेब से टैक्स देने का आदी है? आज भी कार्ड से भुगतान करो तो अधिकतर व्यापारी दो प्रतिशत अतिरिक्त जबरन ले लेते हैं या फिर नगद ही लेते हैं। सरकार कागज पर लिख देगी कि व्यापारी ग्राहक पर बोझ नहीं डालेगा, पर जमीन पर कौन रोकेगा? फिर वही काला धन, वही कैश का खेल शुरू।

फिर देश के सभी बैंक तो भारी मुनाफे में हैं। स्टेट बैंक ने पिछले साल साठ हजार करोड़ का मुनाफा दिखाया। ये और टैक्स किस बात का ले रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तो क्या अब तक यूपीआई असुरक्षित चल रहा था? अगर असुरक्षित था तो इतना प्रचार क्यों किया? और अगर सुरक्षित था तो अब नया खर्चा कौन सा आ गया? ये सही है कि पहले की सरकारें मनीआर्डर, ड्राफ्ट या और वित्तीय सेवाओं पर अतिरिक्त राशि लेती रहीं हैं और इसीलिए तो देश ने उनसे मुक्ति पाई और आपको सिंहासन दिया। अगर सरकार डिजिटल को बढ़ावा देना चाहती है तो उस पर इनाम दे , सजा नहीं। आज यूपीआई दुनिया के लिए एक मॉडल है. उसी मॉडल को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है ।

विद्यालयों के ...

डॉ0 सीमा गुप्ता

'ऑपरेशन कायाकल्प' से परिषदीय शिक्षा का रूपांतरण

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़, आधुनिक और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कायाकल्प' एक युगांतरकारी पहल के रूप में स्थापित हुआ है। वर्ष 2017 के पश्चात परिषदीय विद्यालयों के भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश के समग्र कायाकल्प का जो अभियान प्रारंभ किया गया, उसके सकारात्मक परिणाम आज धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कभी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के अभाव तथा सीमित संसाधनों से जूझने वाले विद्यालय अब आधुनिक तकनीक और सुदृढ़ अधोसंरचना से युक्त होकर प्रेरक शिक्षण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। इस राज्यव्यापी नीतिगत अभियान के अंतर्गत जनपद भदोही ने प्राथमिक शिक्षा के आधुनिकीकरण और विद्यालयी सुदृढ़ीकरण में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। जिला प्रशासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग के परस्पर समन्वय से जनपद के नगरीय और सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को आधुनिक मानकों के अनुरूप सज्जित किया गया है। कभी टाट-पट्टी पर बैठकर अध्ययन करने की विवशता को समाप्त करते हुए विद्यार्थियों को गरिमापूर्ण और अनुकूल शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है।'ऑपरेशन कायाकल्प' की मूल शक्ति अंतर-विभागीय समन्वय (कन्वर्जेंस) की सुविचारित कार्यप्रणाली में निहित है। पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त संसाधनों को एकीकृत कर परिषदीय विद्यालयों को निर्धारित 19 अनिवार्य अवस्थापना मानकों से संतृप्त करने का वृहद अभियान संचालित किया गया। इस समेकित प्रयास के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की विकास निधियों का प्रभावी उपयोग विद्यालयी ढांचे को सुदृढ़ करने में सुनिश्चित किया गया।

जनपद भदोही के विद्यालयों में अवस्थापना मानकों के संतृप्तीकरण के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक, क्रियाशील और टाइल्सयुक्त शौचालयों का निर्माण कराया गया है। विद्यालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति (रनिंग वाटर) की व्यवस्था, सबमर्सिबल पंपों की स्थापना तथा विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए विशेष मल्टीपल हैंडवाशिंग यूनिट्स स्थापित की गई हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता शत-प्रतिशत परिसरों में सुनिश्चित की गई है।

विद्यालयों के भौतिक परिवेश को आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए कक्षाओं के टाइल्स वाले फर्श का संपूर्ण टाइलीकरण, निर्बाध विद्युतीकरण, उच्च गुणवत्ता वाले पंखे तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया है। परिसर की सुरक्षा हेतु पक्की चारदीवारी और मुख्य द्वारों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग विद्यार्थियों) के सुगम आवागमन हेतु बाधारहित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से मानक के अनुरूप रैंप और रेलिंग का निर्माण कराया गया है। अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ भदोही में तकनीक-आधारित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ नींव रखी गई है।

निरामय यौवन

हर मानव चाहता है कि उसका जीवन निरामय यौवन से भरपूर रहे । जर्जर कस्ती के सहारे तूफानों से लडने का इरादा जीवन में अन्त तक रहे । लडखडा रहे हैं कदम पर दूर तक चलने का वादा भितर में रहे । कैसे कोई जी सकता है निरोग, निरामय,आनन्द का जीवन ? जब जीवनशैली के प्रतिजागरूकता कम,उदासीनता ज्यादा है। जीवन का यही है संघर्ष मन के पिछे भागे तो होगा अजीब विरोधाभास ।आत्मा जागे तो होगा सही पुरूषार्थ।जीवन जीने का सही फार्मुला होगा हमारे पास। स्वस्थता ,संतुष्टि,कम खाना,गम खाना, नम जाना ,प्रातः भ्रमण,परोपकार,कषायविजय आदि गुणों का विकास हो हमारे अंदर । जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को समुज्ज्वल बनाएं । सद्व्यवहार करने वाले के हृदय में उसका ही सव्यवहार उसे सुख,आनन्द एवं,पुष्प की शाश्वत सुगन्ध प्रदान करके उसके जीवन में यश एवं कीर्ति रूपी सुगन्ध को प्रत्येक दिशा में द्विगुणित कर देता है। अतः हम जैसे कर्म करते है हमें उसका वैसा ही फल मिलता है ।हमारे द्वारा किये गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते है। जर्जर कस्ती के सहारे तूफानों से लडने का इरादा है। लडखडा रहे हैं कदम पर दूर तक चलने का वादा है। आत्मा जागे तो होगा सही पुरूषार्थ। जीवन जीने का सही फार्मुला होगा हमारे पास। हम यदि सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे जीवन में पद,प्रतिष्ठा और पैसा जबकि यह सही में कुछ काम के नहीं हैं यदि तुष्टि , संतुष्टी और कोई अपना नहीं।खुशियाँ नहीं मिलती पैसों से मिलती हैं अपनों के अपनत्व से।जीवन है आनंद के लिए न कि तनाव लेकर दौड़-धूप करते-करते ही मरने के लिए। जिनमें उत्साह उमँग होता है जिनकी इच्छाशक्ति व संकल्पशक्ति मजबूत होती है ऐसे व्यक्तियों के सामने उम्र कोई बाधा नहीं होती है ।ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे हुयें होते है जो असंभव को भी संभव बना देते है। यौवन है जीवन को हमारे द्वारा पूर्णतः उत्साह से भरा अनुभव करना। भीतर एक अलग ही प्रबल इच्छा शक्ति का लक्षण है यौवन । भितर में हरदम कुछ नया करने की कुलबुलाहट है यौवन ।

› प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

वस्त्र रंगाई से ...

जसपाल सिंह

फास्ट फैशन की चमक और पर्यावरण की कीमत

आज फैशन केवल पहनावे की जरूरत नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी जीवनशैली और सामाजिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और लगातार बदलते ट्रेंड ने कपड़ों की खरीदारी को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। कम कीमत में नया डिजाइन मिल जाना आकर्षक जरूर है, लेकिन इस सुविधा की पर्यावरणीय कीमत लगातार बढ़ रही है।

फास्ट फैशन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कपड़ा हमें बहुत सस्ता दिखाई देता है, वह वास्तव में पर्यावरण के लिए कितना महंगा है?

इस सवाल का जवाब दुनिया भर में हुए कई वैज्ञानिक अध्ययनों में मिलता है।

शोध ने बताई फैशन उद्योग की वास्तविक कीमत

वर्ष 2020 में Nature Reviews Earth & Environment में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण समीक्षा अध्ययन में किरसी नीनिमाकी और उनके सहयोगियों ने फैशन उद्योग के पर्यावरणीय प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया। शोध में उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक कपड़ों की पूरी श्रृंखला में पानी की खपत, रासायनिक प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन और कपड़ा-कचरे का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के अनुसार फैशन उद्योग हर वर्ष 92 मिलियन टन से अधिक कपड़ा-कचरा पैदा करता है और लगभग 79 ट्रिलियन लीटर पानी की खपत करता है। शोधकर्ताओं ने उत्पादन की गति कम करने, कपड़ों की उपयोग-अवधि बढ़ाने और टिकाऊ फैशन की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह आंकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक नया कपड़ा खरीदते समय हम केवल उसकी कीमत नहीं चुका रहे होते, बल्कि उसके पीछे इस्तेमाल हुए पानी, ऊर्जा, कच्चे माल और परिवहन की पर्यावरणीय लागत भी कहीं न कहीं जुड़ी होती है।

जल प्रदूषण पर भी गंभीर असर

फास्ट फैशन की समस्या केवल कपड़ा-कचरे तक सीमित नहीं है। कपड़ों की रंगाई और फिनिशिंग में बड़ी मात्रा में पानी तथा विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल होता है। यदि औद्योगिक अपशिष्ट जल का उचित उपचार नहीं किया जाए तो ये रसायन नदियों और अन्य जल स्रोतों तक पहुंच सकते हैं।

2022 में Water जर्नल में प्रकाशित एक systematic review में शोधकर्ताओं ने 1996 से 2021 के बीच प्रकाशित हजारों अध्ययनों की समीक्षा की और उनमें से 65 प्रासंगिक अध्ययनों का विस्तृत विश्लेषण किया। इस समीक्षा में फैशन और वस्त्र उद्योग को पानी की खपत, अपशिष्ट जल तथा जल-गुणवत्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती के रूप में देखा गया। अध्ययन ने टिकाऊ उत्पादन, बेहतर अपशिष्ट जल उपचार और circular economy की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

वस्त्र रंगाई से संबंधित एक अन्य समीक्षा में भी बताया गया है कि पारंपरिक dyeing प्रक्रिया में रंग, नमक, surfactants और अन्य रसायन अपशिष्ट जल में पहुंच सकते हैं और जल-प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं।

कपड़े धोने से भी निकलता है माइक्रोप्लास्टिक

फास्ट फैशन का एक ऐसा प्रभाव है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते—माइक्रोफाइबर प्रदूषण।

पॉलिएस्टर, नायलॉन और ऐक्रेलिक जैसे सिंथेटिक कपड़े प्लास्टिक आधारित रेशों से बनाए जाते हैं। इन्हें पहनने और विशेष रूप से धोने के दौरान अत्यंत छोटे रेशे निकल सकते हैं और पानी के माध्यम से पर्यावरण में पहुंच सकते हैं। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार सिंथेटिक वस्त्रों की धुलाई माइक्रो-प्लास्टिक प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एजेंसी के आकलन के अनुसार दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 2 लाख से 5 लाख टन तक textile microplastics समुद्री पर्यावरण में पहुंच सकते हैं।

यूरोपीय संघ के 2019 के आंकड़ों पर आधारित एक अन्य आकलन में सिंथेटिक वस्त्रों से पर्यावरण में 1.6 से 61.1 किलो टन माइक्रोप्लास्टिक के अनजाने में छोड़े जाने का अनुमान लगाया गया।

इसलिए यह समझना जरूरी है कि कपड़ा पर्यावरण को केवल तब प्रभावित नहीं करता जब वह फैक्ट्री में बन रहा होता है या कूड़ेदान में फेंका जाता है। उसके जीवनकाल के दौरान भी पर्यावरणीय प्रभाव जारी रह सकता है।

सबसे बड़ी समस्या है 'जल्दी खरीदो, जल्दी बदलो' की संस्कृति

फास्ट फैशन का कारोबार तेजी से बदलते ट्रेंड और लगातार खरीदारी पर आधारित है। आज जो डिजाइन लोकप्रिय है, कुछ ही सप्ताह बाद वह पुराना लग सकता है। ऑनलाइन सेल और कम कीमतें उपभोक्ताओं को बार-बार खरीदारी के लिए प्रेरित करती हैं।

यही कारण है कि कपड़ों का उपयोगकाल कम होता जा रहा है। अच्छी स्थिति में मौजूद कपड़े भी केवल इसलिए त्याग दिए जाते हैं क्योंकि उनका डिजाइन पुराना हो गया है।

इससे दोहरी समस्या पैदा होती है—एक ओर नए कपड़े बनाने के लिए पानी, ऊर्जा और कच्चे माल की मांग बढ़ती है और दूसरी ओर पुराने कपड़ों का कचरा बढ़ता जाता है।

इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है। कपड़ा कंपनियों की उत्पादन प्रणाली और पर्यावरणीय प्रबंधन की बड़ी भूमिका है, लेकिन उपभोक्ता की खरीदारी की आदत भी महत्वपूर्ण है।

यदि हम जरूरत से अधिक कपड़े खरीदते हैं, कम समय तक इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं तो बाजार में लगातार नए उत्पादन की मांग पैदा होती है।

इसलिए समाधान केवल उद्योग में बदलाव से नहीं आएगा। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव भी उतना ही आवश्यक है।

फास्ट फैशन पर अधिकांश चर्चाएं वैश्विक आंकड़ों के आधार पर होती हैं, लेकिन भारत के शहरों में स्थानीय स्तर पर भी इस विषय पर अध्ययन की काफी संभावनाएं हैं।

बरेली, मेरठ जैसे शहरों में कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सर्वेक्षण के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि एक परिवार वर्ष में कितने कपड़े खरीदता है, पुराने कपड़ों का क्या करता है, कितने कपड़े वास्तव में नियमित रूप से पहने जाते हैं और खरीदारी में कीमत, ब्रांड, सोशल मीडिया तथा फैशन ट्रेंड की क्या भूमिका है।

ऐसे स्थानीय अध्ययन से यह भी पता लगाया जा सकता है कि सूती और सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग किस अनुपात में हो रहा है तथा पुराने कपड़ों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की स्थिति क्या है।

पेड़ पर लटके मिले युवक-महिला के शव

पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही

आत्महत्या

तमसा संकेत, एजेंसी

नरवल/कानपुर। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे लाइन के किनारे एक ही पेड़ पर युवक और महिला के शव लटके मिले। घटना की जानकारी उस समय हुई, जब ग्रामीणों ने पेड़ पर शवों को देखा। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के सुभौली गांव के पास का बताया जा रहा है। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे ग्रामीण रेलवे लाइन के किनारे

से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पेड़ पर लटके युवक और महिला के शवों पर पड़ी।

महिला का आधार कार्ड और फोन मिला

घटनास्थल से एक पॉलीथिन मिली, जिसमें बाइक की चाबी, महिला का आधार कार्ड और एक कीपैड मोबाइल फोन मिला। मोबाइल से सिम निकला हुआ था। पॉलीथिन से 4200 रुपए नकद, जबकि युवक की पैंट की जेब से 200 रुपए मिले। आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने महिला के परिजनों से संपर्क किया। उसकी बहन ने महिला की पहचान मालती के रूप में की। उसने बताया कि मालती की करीब आठ साल पहले शादी हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। वह तीन दिन पहले घर से लापता हो गई थी।

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने की जांच-पड़ताल

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे डायल-112 पुलिस को सूचना मिली थी कि सुभौली गांव से करीब एक किलोमीटर दूर रेलवे लाइन किनारे बबूल के पेड़ से एक पुरुष और महिला का शव लटका है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू किया। दोनों की मौत की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है। दोनों शव एक ही पेड़ पर लटके होने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के इलाके की भी जांच की।

महिला के कपड़ों से पुलिस को उसका आधार कार्ड बना है, इससे उसकी पहचान हुई है।

हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही पुलिस

पुलिस के अनुसार, युवक की पहचान ओम के रूप में हुई है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई है। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सामान को सुरक्षित कर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और युवक के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

एक ही पेड़ पर युवक और महिला के शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।

डीपफेक से सियासत नहीं, लोकतंत्र कमजोर होता है : डॉ. राजेश्वर सिंह

'सस्ती लोकप्रियता से व्यूज़ मिल सकते हैं, वोट नहीं'

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एआई तकनीक से तैयार वीडियो और डीपफेक के इस्तेमाल को लेकर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध विचारों और नीतियों के स्तर पर होना चाहिए, किसी व्यक्ति की छवि बिगाड़ने के लिए फर्जी डिजिटल सामग्री का सहारा लेना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में ऐसी सामग्री के प्रदर्शन की खबरों को उन्होंने सार्वजनिक जीवन की गरिमा के लिए चिंताजनक बताया।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को बदनाम करने के लिए डीपफेक तैयार करना या उसका प्रसार करना राजनीतिक रणनीति नहीं है। लोकतंत्र में नीतियों पर असहमति, जनप्रतिनिधियों के काम पर सवाल और उपलब्धियों के दावों की आलोचना पूरी तरह जायज है, लेकिन झूठी और भ्रामक सामग्री के जरिए किसी की छवि प्रभावित करना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सस्ती लोकप्रियता से Views तो मिल सकते हैं, Votes नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और नेताओं का मूल्यांकन उनके कार्य, ईमानदारी और आचरण से करती है, फर्जी और तोड़-मरोड़कर बनाए गए वीडियो से नहीं।" विधायक ने सभी राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों से अपील की कि चुनावी प्रतिस्पर्धा विकास, नीतियों, विचारों और जनसेवा के मुद्दों पर हो।

फास्ट न्यूज

व्यापारियों ने यूपीआई शुल्क के विरोध में प्रदर्शन किया

बलिया। बलिया कलेक्ट्रेट में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में किया गया। व्यापारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र भी जिलाधिकारी (डीएम) के प्रतिनिधि को सौंपा। कि भारत सरकार ने यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर व्यापार और लेन-देन को आसान बनाने के लिए अहम कोशिशें की हैं।

पंकज केसरवानी रामपुर में वाहन चेकिंग व्यवस्था विवाद

रामपुर। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की प्रदेश कैंप कार्यालय पर पंचायत हुई। इसमें वाहन चेकिंग व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के समक्ष जांच की मांग रखी। प्रदेश महासचिव हसीब अहमद और जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने वाहन चेकिंग से संबंधित प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर रोड पर महिला थाने से रोडवेज तक अलग-अलग स्थानों पर की जा रही चेकिंग के संबंध में चेकिंग आईडी और लॉगिन रिकॉर्ड की जांच कराई जाए।

यूपी में विधायक पूजा पाल से 1.55 लाख की ठगी

कौशांबी। कौशांबी की चायल सीट से विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल के बैंक खाते से करीब 1.55 लाख रुपए निकाल लिए गए। 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच कई बार रकम निकाली गई। ये लेनदेन फोन-पे और UPI के जरिए किए गए। 14 सितंबर को विधायक को इसकी जानकारी हुई। बैंक खाते की जांच कराने पर कई ऐसे लेन-देन मिले, जो उनकी जानकारी के बिना किए गए थे।

रावल में राधा अष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब

जन्मस्थली पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। राधा रानी की जन्मस्थली रावल शनिवार को भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। राधा अष्टमी पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर-दराज से पहुंचे भक्तों ने राधा रानी के दर्शन कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर दिनभर राधे-राधे के जयकारों से गूंजता रहा।

राधा रानी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के बाद पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जन्मस्थली पर राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

मंदिर और आसपास का क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर रहा।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए।

पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी की गई।

श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण माहौल में राधा रानी के दर्शन किए। पुजारी बोलेः राधा रानी की जन्मस्थली रावल में राधा अष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

3 हजार वर्गमीटर सरकारी जमीन कब्जामुक्त, भारी पुलिस फोर्स के बीच बाउंड्री ढहाई

कानपुर में कब्रिस्तान पर चला केडीए का बुलडोजर

तमसा संकेत, एजेंसी

- कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलने के बाद मौके पर पहुंची भीड़।
- कार्रवाई करने से पहले बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स के बीच कब्रिस्तान की अवैध जमीन पर बुलडोजर चला।
- बुलडोजर ने अवैध बने बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया।

कानपुर। कानपुर में केडीए की टीम ने शनिवार सुबह अतिक्रमण कर बनाए गए कब्रिस्तान के हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध और हंगामा किया। हालांकि, भारी पुलिस फोर्स और पीएसी की मौजूदगी में अतिक्रमण अभियान तेजी से चलाया गया। यह कार्रवाई बर्रा-6 थाना क्षेत्र में हुई। केडीए की टीम ने कब्रिस्तान की बाउंड्री और कब्रों के ऊपर बने चबूतरों को ढहा दिया। हालांकि, किसी भी कब्र को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। केडीए अफसरों के मुताबिक, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की गई।

केडीए के ओएसडी सत शुक्ला ने बताया- बर्रा-6 में पाल टावर के सामने ग्राम बरी की आराजी संख्या-314 से जुड़ी करीब 3 हजार वर्गमीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बना दिया गया था। करीब 30 से 35 साल से इस जमीन पर कब्जा था। कब्रिस्तान के ठीक ऊपर से मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू हुआ तो मामला केडीए तक पहुंचा। इसके बाद केडीए अफसरों ने जमीन की जांच-पड़ताल की। जांच में सामने आया कि केडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान बनाया गया था।

नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

केडीए के ओएसडी शत शुक्ला ने बताया-जोन-3 स्थित भूमि बैंक अनुभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26(क)(4) के तहत नोटिस जारी किया गया था।

संबंधित पक्ष से जमीन और निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था।

हंगामे के बीच गरजता रहा केडीए का बुलडोजर

केडीए की टीम ने कार्रवाई शुरू की तो मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी समेत सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने केडीए की कार्रवाई को अवैध बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद केडीए के ओएसडी ने लोगों को बताया कि यह केडीए की जमीन है और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद केडीए की टीम ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने देखते ही देखते बाउंड्री वॉल गिरा दी और मौके पर बने अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए।

कार्रवाई के दौरान पुलिस, पीएसी और महिला पुलिस बल की तैनाती के चलते विरोध ज्यादा देर तक नहीं चल सका।

लंपी स्किन डिजीज से अब तक 9,003 पशु प्रभावित, 16.08 लाख से अधिक पशुओं का हुआ टीकाकरण

योगी सरकार ने लंपी वायरस की रोकथाम के लिए 25 जनपदों में 606 टीमें कीं तैनात

- 25 से 29 सितंबर तक काशी के शास्त्रीय सुर से बुंदेलखंड के राई और अवध की सूफियाना शाम आदि की सजेगी महफिल
- योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मिल रहा अवसर

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशुधन को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने के लिए रोकथाम और नियंत्रण अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश के 25 जनपदों में 606 टीमें तैनात की गई हैं। टीमें प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी, उपचार और टीकाकरण का काम कर रही हैं। विभाग का फोकस संक्रमण की समय पर पहचान करने के साथ प्रभावित पशुओं को उपचार उपलब्ध कराने और स्वस्थ पशुओं को संक्रमण से बचाने पर है। अपर मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पशु चिकित्सक निर्धारित समय पर चिकित्सालयों में मौजूद रहें। इसके साथ ही गांवों में शिविर लगाकर टीकाकरण अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। पशु सखी, पैरावेट और मैत्री को आवश्यक प्रशिक्षण देकर टीकाकरण की शत-प्रतिशत सुनिश्चितता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए तैनात 606 टीमें प्रभावित जनपदों में गांव-गांव जाकर पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। टीमों की ओर से पशुपालकों को बीमारी के लक्षण, बचाव के उपाय और संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की जानकारी दी जा रही है। संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा टीमों को तत्काल सक्रिय किया जा रहा है। विभाग ने जनप्रतिनिधियों, गोपालकों और गोशाला संचालकों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन बैठकों के माध्यम से पशुपालकों को बीमारी से बचाव और संक्रमण की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है। त्वेक गो आश्रय स्थल में हरे चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

16.08 लाख पशुओं का हुआ टीकाकरण

विभागीय अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 16,08,548 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण से अब तक 9,003 पशुओं के प्रभावित होने की सूचना है। प्रभावित पशुओं की पहचान के बाद उनके उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पशुधन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने प्रभावित जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने रिंग वैक्सीनेशन, संक्रमित पशुओं को अलग रखने, वेक्टर कंट्रोल, कीटाणुशोधन और साफ-सफाई जैसे उपायों को प्राथमिकता देने को कहा है। साथ ही टीकाकरण अभियान की नियमित समीक्षा करने और इसे व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

टीकाकरण पर दिया जा रहा विशेष जोर

लंपी स्किन डिजीज के नियंत्रण में टीकाकरण को महत्वपूर्ण उपाय मानते हुए विभाग द्वारा प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 16 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही पशुपालकों से अपील की जा रही है कि वे अपने पशुओं का समय से टीकाकरण कराएं और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल निकटतम पशु चिकित्सालय अथवा विभागीय टीम को सूचना दें।

विभाग की ओर से पशुपालकों को पशुओं के आसपास साफ-सफाई रखने और मच्छर-मक्खी जैसे वाहक कीटों की रोकथाम करने की सलाह दी जा रही है। पशुओं के शरीर पर गांठें, बुखार, त्वचा पर घाव या कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सक से जांच कराने को कहा गया है। विभाग का लक्ष्य समय रहते संक्रमण की पहचान, निगरानी, टीकाकरण और उपचार के जरिए बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करना है।

कूटरचित दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोपी गिरफ्तार

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। बिजनौर थाना पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी तरीके से विक्रय करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस के मुताबिक, बदाली खेड़ा निवासी पूनम पाल ने 12 अगस्त 2026 को बिजनौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन्द्रजीत गिरी, ममता और राम गोपाल ने उनकी सेक्टर-जी, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित भूमि को हड़पने के उद्देश्य से कूटरचित अभिलेख तैयार किए और फर्जी गवाह खड़े कर जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। शिकायतकर्ता द्वारा रुपये मांगने पर इन्द्रजीत गिरी द्वारा जान-माल की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। मामले में बिजनौर थाने में मुकदमा संख्या 214/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था। तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से पुलिस ने इन्द्रजीत गिरी पुत्र स्वर्गीय भागीरथी गिरी, निवासी आशियाना एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उम्र करीब 58 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने जमीन हड़पने के लिए साथियों के साथ षड्यंत्र करने तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने की बात स्वीकार की।

ट्रेडीशन संग ट्रेडः ग्लोबल मेहमानों के सामने सजेगा यूपी की संस्कृति का 'महाकुंभ'

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 25 से 29 सितंबर तक विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश को निवेश, व्यापार और पर्यटन के साथ-साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। ट्रेड शो में देश-विदेश से आने वाले उद्यमियों, निवेशकों और आगंतुकों को प्रदेश की लोक कलाओं, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। पांच दिनों में सजेगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की महफिल ट्रेड शो के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत 25 सितंबर को शंख वादन एवं वैदिक मंगलाचरण से होगी। वाराणसी के विशाल कुमार की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद नोएडा के पं. चेतन जोशी का वाद्य संगीत, लखनऊ की अलोकनिशा श्रीवास्तव का कथक नृत्य, प्रयागराज की पूर्णिमा का ढेढ़िया लोक नृत्य और वृंदावन की आरती खेतपाल की भजन प्रस्तुति दर्शकों को आकर्षित करेगी। 26 सितंबर को पखावज युगल, भोजपुरी लोक गायन, कथक, मथुरा का लोक नृत्य और स्टार नाइट का आयोजन होगा। पखावज युगल में दिल्ली के पं. रविशंकर उपाध्याय एवं पं. ऋषि शंकर उपाध्याय प्रस्तुति देंगे। भोजपुरी लोक गायन में मिर्जापुर की कुसुम पांडेय, जौनपुर के अवनीश तिवारी और कथक में नोएडा की मर्यादा कुलश्रेष्ठ शामिल होंगी। मथुरा की सीमा मावल लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगी और सुल्तानपुर की निष्ठा शर्मा स्टार नाइट में प्रस्तुति देंगी। 27 सितंबर को सैक्सोफोन वाद्य संगीत, भजन/लोक गायन, झांसी का राई लोक नृत्य, भरतनाट्यम और स्टार नाइट का आयोजन किया जाएगा। 28 सितंबर को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का परकशन एन्सेंबल, महोबा के जितेंद्र चौरसिया का आल्हा गायन, कथक, पीलीभीत का थारू जनजातीय नृत्य और सुल्तानपुर की रूपाली जोग्गू की सूफी नाइट आयोजित होगी।

यूपीआई शुल्क के विरोध में 'आप' का प्रदर्शन

लखनऊ में कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। डिजिटल भुगतान (UPI) पर 0.4% नया टैक्स थोपकर गरीब, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग की जेब पर महंगाई का एक और बोझ डालने वाली जनविरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी 'व्यापार प्रकोष्ठ' उत्तर प्रदेश ने आप उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जोरदार हल्ला बोल और विशाल प्रदर्शन किया। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा समेत सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि सरकार ने अब चुपके से यूपीआई (UPI) पर 0.4% टैक्स लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी, विनम्रता और सादगी से इसे धीरे से देश पर थोप दिया गया, ताकि जनता को इसकी भनक तक न लगे।

पेयजल, शौचालय और गौशालाओं में अनियमितता का आरोप, डीएम से जांच की मांग

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर विकासखंड की विभिन्न ग्रामसभाओं में पेयजल, शौचालय और गौशालाओं से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा गया है। ग्राम जैतीखेड़ा निवासी संजीव मिश्रा भाजपा जिला मंत्री ने शिकायत में विकासखंड अधिकारियों और ग्राम सचिवों पर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू न करने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं।

शिकायती पत्र के अनुसार परवर पश्चिम, माती, परवर पूरब, सोहावा, मनौरा, सोसीरनखेड़ा, बीबीपुर, नाजीरखेड़ा, गढ़ी, मवैय्या, बाबूखेड़ा, खोला, कंथी, जैतीखेड़ा, नीवां, साढ़ल्लाहखेड़ा, चंद्रावल सहित कई ग्रामसभाओं और उनके मजरों में पेयजल के लिए लगाए गए हैंडपंप व नल लंबे समय से खराब पड़े हैं। आरोप है कि इनकी मरम्मत और रखरखाव कागजों तक सीमित है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने महिलाओं के लिए बनाए जाने वाले इज्जत घर एवं शौचालयों की योजनाओं में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आश्वासन तो मिलता है, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।

वहीं, गौशालाओं में गोवंश के लिए मिलने वाले अनुदान के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि पर्याप्त भूसा-पानी नहीं मिलने से गोवंश की मौतें हो रही हैं और मृत पशुओं के निस्तारण में भी लापरवाही बरती जा रही है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों व संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई तथा ग्रामसभाओं में पेयजल, शौचालय और गौशाला संबंधी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की है।

आगरा में जनकपुरी महोत्सव के ब्रोशर में 7 ऑफर, आयोजन समिति बोली-हमें पता ही नहीं

5 लाख रुपए में श्रीराम और सीता की आरती

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा के प्रमुख धार्मिक आयोजन जनकपुरी महोत्सव 2026 के लिए चंदा जुटाने का नया तरीका निकाला गया है। 5 लाख रुपये देने वाले को भगवान श्रीराम और सीताजी के स्वरूपों की आरती करने और मंच पर सम्मानित करने का ऑफर दिया जा रहा है। आगरा की गौरवशाली धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के लिए इस तरह चंदा जुटाने का तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, ब्रोशर को लेकर उठे सवालों के बीच आयोजन कमेटी अब अपना पल्ला झाड़ रही है। आगरा के एतिहासिक जनकपुरी महोत्सव का आयोजन सिकंदरा भावना एस्टेट क्षेत्र में होने जा रहा है। 7, 8 और 9 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विशाल जनकमहल बनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में रास्तों की मरम्मत और लाइट व्यवस्था ठीक करने का काम

किया जा रहा है। जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत 1964 में हुई थी। इस आयोजन में आगरा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। विकास कार्यों को छोड़कर क्षेत्र में सजावट, जनकमहल निर्माण जैसे काम आयोजन कमेटी द्वारा कराए जाते हैं। इसके लिए सहयोग राशि जुटाई जाती है। चंदा जुटाने के लिए इस बार पैकेज में श्रीराम और सीता की आरती का भी ऑफर दिया गया है। स्पॉन्सरशिप पैकेज के माध्यम से रकम जुटाई जा रही है। इसके लिए स्पॉन्सर्स को ब्रोशर भेजे जा रहे हैं। इसमें उन्हें तरह-तरह के ऑफर दिए गए हैं। उन्हें बताया गया कि 5 लाख रुपये की स्पॉन्सरशिप देने पर उन्हें महोत्सव के दौरान क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ये 7 सुविधाएं देने का ऑफर

1. विशेष स्वागत एवं सम्मान
जनकपुरी महोत्सव में आपके आगमन पर आपका विशेष स्वागत एवं गरिमापूर्ण सम्मान किया जाएगा तथा आपको स्मृति-चिह्न भेंट किया जाएगा।

2. भगवान श्रीराम एवं सीता माता की आरती का सौभाग्य
जनकपुरी महोत्सव के इस पावन अवसर पर आपको भगवान श्रीराम एवं सीता माता की आरती करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होगा। यह आपके लिए इस दिव्य एवं भव्य आयोजन से जुड़ने का अत्यंत गौरवपूर्ण एवं स्मरणीय अवसर होगा।

3. ब्रांडेड गेट
जनकपुरी महोत्सव परिसर में आपके नाम/संस्था/ब्रांड की ब्रांडिंग हेतु गेट स्थापित किया जाएगा।

4. दो विशेष स्टॉल
महोत्सव परिसर में आपके संस्थान/ब्रांड के प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन एवं जनसंपर्क हेतु 2 विशेष स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. LED स्क्रीन पर विज्ञापन
महोत्सव के दौरान प्रमुख स्थानों पर लगी LED स्क्रीन पर आपके संस्थान/ब्रांड का विज्ञापन प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों तक आपके ब्रांड की पहुंच सुनिश्चित होगी।

6. जनकपुरी महोत्सव 2026 की मैगज़ीन में स्थान
महोत्सव के अवसर पर प्रकाशित होने वाली विशेष 'जनकपुरी महोत्सव 2026' मैगज़ीन में आपके संस्थान/ब्रांड की जगह प्रकाशित की जाएगी।

7. प्रचार एवं ब्रांड विजिबिलिटी
महोत्सव की विभिन्न प्रचार गतिविधियों एवं आयोजन स्थलों पर आपके सहयोग/ब्रांड को विशेष दृश्यता एवं प्रचार प्रदान किया जाएगा।

मुरादाबाद में 4 तहसीलदारों के ट्रांसफर

मुरादाबाद। मुरादाबाद में जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने 4 तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में अंकित तोमर को सदर और धीरेश कुमार सिंह को बिलारी का तहसीलदार बनाया गया है।

अंकित तोमर सदर तहसील में ही तहसीलदार न्यायकि के पद पर तैनात थे।

उन्हें प्रमोट करके सदर तहसीलदार बनाया गया है।

मुरादाबाद सदर तहसील के तहसीलदार राजकुमार को अब ठाकुरद्वारा का तहसीलदार न्यायिक बनाया गया है।

धीरेश कुमार सिंह ठाकुरद्वारा में तहसीलदार न्यायिक के पद पर तैनात थे।

इस बदलाव में बिलारी के तहसीलदार अवनीन्द्र कुमार शुक्ल को मुरादाबाद सदर तहसील में तहसीलदार न्यायिक बनाया गया है।

संत प्रेमानंद महाराज ने मनाया राधा रानी का प्राकट्य उत्सव

यमुना बिहार आश्रम से केली कुंज पहुंचे, दर्शन के लिए लगी भीड़

तमसा संकेत, एजेंसी

मथुरा। राधा अष्टमी पर शनिवार को संत प्रेमानंद महाराज ने रमनरेती स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचकर लाडली जी का प्राकट्य उत्सव मनाया। वह वेलवन स्थित यमुना बिहार कुंज आश्रम से केली कुंज पहुंचे। उनके दर्शनों के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि करीब एक किलोमीटर तक रास्ते में भक्त ही भक्त नजर आए। संत प्रेमानंद महाराज कुछ दूरी तक गाड़ी से पहुंचे। इसके बाद भक्तों की भीड़ और उनकी भावनाओं को देखते हुए वह गाड़ी से उतर गए और पैदल ही केली कुंज आश्रम तक गए। इस दौरान भक्त लगातार राधे-राधे के जयकारे लगाते रहे और उन्हें लाडली जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई देते रहे। राधा अष्टमी पर केली कुंज में विराजमान राधारानी का खास श्रृंगार किया गया। उन्हें अलग-अलग रंगों की आकर्षक पोशाक पहनाई गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राधारानी गुलाबी रंग की पोशाक में नजर आईं। वहीं आश्रम के यूट्यूब चैनल पर चल रहे लाइव राधा नाम कीर्तन में वह सफेद पोशाक में दिखाई दीं। एक अन्य वीडियो में मंगला आरती के दौरान राधारानी लाल रंग की पोशाक और पीले दुपट्टे में नजर आईं। आश्रम को भी फूलों से सजाया गया था। केली कुंज आश्रम पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज ने राधारानी की सेवा की। इसके बाद वहां चल रहे राधा नाम कीर्तन में वह भी शामिल हुए। काफी देर तक वह अपने स्थान पर बैठकर राधा नाम का जाप करते रहे।

फास्ट न्यूज

ढाबे पर विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग

आगरा। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ढाबे पर मामूली विवाद के बाद फायरिंग से दहशत फैल गई। दयालबाग रोड स्थित ढाबे पर खाना खाने आए चार युवकों में विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर कई राउंड फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि उसने पूरी मैगजीन खाली कर दी। इसके बाद वह दोबारा पिस्टल लोड करने लगा, तभी आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी।

पानी के लिए जाम लगाया, युवक मेट्रो पुल पर चढ़ा

आगरा। आगरा में पनी की समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने एमजी रोड पर जाम लगा दिया। एक युवक मेट्रो के निर्माणाधीन एलिवेटेड ट्रैक पर चढ़ गया। लगभग आधा घंटे तक वह ट्रैक पर बैठा रहा। पुलिस के समझाने के बाद वह नीचे उतरा। एमजी रोड स्थित धाकरान चौराहे पर मेट्रो के निर्माणाधीन एलिवेटेड ट्रैक पर पवन धाकड़ नाम का युवक चढ़ गया है। आत्महत्या की धमकी दे रहा है। उसका कहना था कि पिछले 6 महीने से क्षेत्र में पानी की समस्या है। समर्थन में महिलाये और पुरुष एमजी रोड पर हैं। जाम लग गया है।

करणी सेना नेता से मारपीट में दो आरोपी जेल गए

अलीगढ़। अलीगढ़ में करणी सेना नेता सचिन राघव पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और टिप्पणियों की संख्या बढ़ गई है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अलग-अलग जगहों से करणी सेना से जुड़े लोग घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी दौरान कुछ पोस्ट में वाल्मीकि समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है।

पुलिस से भी बदसलूकी, एएसपी ने मौके पर फटकारे शराबी, छह से ज्यादा लोग हिरासत में

अलीगढ़ में इंडिया बार में शराबियों ने किया हंगामा

तमसा संकेत, एजेंसी

अलीगढ़। गांधी पार्क थाना क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड के पास स्थित इंडिया बार में बीती देर रात शराब के नशे में युवकों ने जमकर हंगामा किया। बार में विवाद और हुड़दंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी युवक शांत नहीं हुए और उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने सख्ती दिखाई और छह से अधिक युवकों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। देर रात तक पुलिस युवकों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाती रही। घटना गांधी पार्क थाना क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड के पास स्थित इंडिया बार की है। बताया जा रहा है।

पुलिस के पहुंचने पर भी नहीं थमा विवाद

बार में हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवकों को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्रता और बदसलूकी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती करते हुए छह से अधिक युवकों को हिरासत में ले लिया और सभी को थाने ले गई। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है।

एएसपी सृष्टि जैन ने मौके पर पहुंचकर लगाई फटकार

मामले की जानकारी मिलने पर एएसपी सृष्टि जैन भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने हंगामा कर रहे युवकों को कड़ी फटकार लगाई और मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एएसपी युवकों को फटकार लगाती नजर आ रही हैं। पुलिस ने मौके से छह से अधिक युवकों को हिरासत में लिया। सभी को गांधीपार्क थाने ले जाया गया। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही हिरासत में लिए गए युवकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इंस्पेक्टर गांधीपार्क राजेश कुमार के अनुसार मामले में दोनों पक्षों पर रात में शराब पीकर मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

बार में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस

बताया जा रहा है कि देर रात इंडिया बार में कुछ युवक शराब पीने के बाद आपस में हंगामा कर रहे थे। शोर-शराबे और विवाद की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवकों को शांत कराने का प्रयास किया।

आरोप है कि इस दौरान कुछ हुड़दंगियों ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की।

इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद युवकों को पकड़ना शुरू कर दिया।

छाता में 116 हेक्टेयर में नई टाउनशिप को हरी झंडी

98 हेक्टेयर जमीन पहले ही जुटा चुका है एमवीडीए, 93 गांव विकास क्षेत्र में होंगे शामिल

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। छाता के विकास को अब नई रफ्तार मिलने की तैयारी है। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक में 116 हेक्टेयर में प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप को मंजूरी दे दी गई। योजना के लिए करीब 98 हेक्टेयर भूमि पहले ही अर्जित की जा चुकी है। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में गीता शोध संस्थान, वृंदावन स्थित यीडा के क्षेत्रीय कार्यालय में हुई बैठक में कृषि भूमि को आवासीय भू-उपयोग में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। छाता में प्रस्तावित टाउनशिप के ड्राफ्ट लेआउट का मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें आवासीय भूखंडों के अलावा ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्शियल,

सामुदायिक और सार्वजनिक उपयोग के भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं। मास्टर प्लान रोड और हरित क्षेत्र भी लेआउट का हिस्सा होंगे। मंडलायुक्त ने लेआउट को मंजूरी देते हुए एक बड़े सेक्टर पार्क का प्रावधान करने के निर्देश दिए। MVDA के विकास क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा। बैठक में 93 गांवों को प्राधिकरण की सीमा में शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य विकास और नियोजन में एकरूपता लाना है। अब प्रस्ताव को शासन स्तर से स्वीकृति दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में MVDA उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन, नगर आयुक्त ओजस्वी राज, सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा, सचिव आशीष सिंह, सह नगर नियोजक स्मिता निगम, अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम सहित बोर्ड सदस्य मौजूद रहे।

नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा

यूपी राइज-2026 में 800 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। युवाओं को नौकरी तलाशने से आगे बढ़ाकर जॉब क्रिएटर बनाने की पहल मथुरा में दिखाई दी। नेशनल हाईवे स्थित जीएलए विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 'यूपी राइज-2026' का आयोजन हुआ। इसमें 800 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं को स्टार्टअप, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि सही आइडिया, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग के जरिए युवा अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यूपी स्टार्टअप फंड, मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग योजना और यूपी स्किल मिशन की जानकारी दी गई। कन्या सुमंगला, फ्री टैबलेट/स्मार्ट-

फोन और महिला सामर्थ्य योजना के तहत उपलब्ध सहायता की भी जानकारी दी गई। प्रतियोगिता में छात्रों ने 25 स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत किए। इनमें से आठ को शॉर्टलिस्ट किया गया। 'बुक माई सारथी', 'कैम्पोरा', 'नमस्ते एआई', 'क्वांटावर्स टेक्नोलॉजीज' और 'दक्ष डायनामिक्स' के आइडिया ने खास ध्यान खींचा। खदानों और सुरंगों जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में बचाव के लिए बनाया गया स्वदेशी 'रोबोडॉग' भी आकर्षण का केंद्र रहा।

जूते में छिपाकर ले गए थे महाराष्ट्र टीईटी के पेपर

आगरा की प्रिंटिंग प्रेस के 3 कर्मचारियों ने 8 हजार के लिए पेपर लीक किया

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का पेपर यूपी में आगरा की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। ठाणे पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पेपर को जूते के सोल में छिपाकर प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला था। इसके लिए आरोपियों को 8 हजार दिए गए थे। साथ ही, उन्हें आगरा में जमीन (प्लॉट) देने का वादा भी किया गया था। ठाणे पुलिस ने शुक्रवार को भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता, प्रिंटिंग प्रेस के 3 कर्मचारियों कर्मचारी नरेश कुमार उर्फ निक्की, बाबूलाल कुशवाहा और संजय शर्मा समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गुप्ता का नाम ओडिशा के एक पेपर लीक मामले में भी सामने आ चुका है। मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि

अशोक साव और प्रकाश मिसाल फरार हैं। 28 जून को होने वाली TET परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया था। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल (MSEC) ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। DCP सिटी अली अब्बास ने बताया- मुंबई पुलिस जांच के सिलसिले में यहां आई थी। लेकिन, उसने क्या कार्रवाई की, इस बारे में जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र में डीसीपी पवन बंसोड़ को सूचना मिली थी कि 3 लोग भिवंडी के एक व्यक्ति को परीक्षा के पेपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कोंगांव इलाके में आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से पेपर के 4 सेट मिले। जांच में महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन (MSCE) के अधिकारियों ने इन्हें असली बताया।

आरोपियों ने ऐसे प्रेस से बाहर पहुंचाए पेपर

जांच के मुताबिक, प्रेस कर्मचारी नरेश कुमार उर्फ निक्की, बाबूलाल कुशवाहा और संजय शर्मा ने प्रश्नपत्र बाहर निकालने की प्लानिंग की। प्रिंटिंग के दौरान जिन प्रश्नपत्रों में स्याही हल्की होती थी या कोई कमी रह जाती थी, उन्हें डिस्पोजल बॉक्स में डाल दिया जाता था।

इन पेपरों की अलग से गिनती नहीं होती थी। बाद में उन्हें नष्ट किया जाना था।

तीनों ने इसी व्यवस्था का फायदा उठाया। चार्जशीट में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताया गया है।

तीनों करीब 12 से 15 हजार रुपए महीने की कमाई करते थे। ऐसे पैसों की लालच में वे पेपर लीक करने के लिए तैयार हो गए प्रेस से बाहर निकाले गए प्रश्नपत्रों को कर्मचारियों ने बिहार के सोनू सिंह तक पहुंचाया।

इसके बाद सोनू ने पेपर मुख्य आरोपी बताए गए बिजेंद्र गुप्ता तक पहुंचाया।

क्या है टीईटी एग्जाम?

- टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के योग्य है या नहीं।
- इस परीक्षा को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (NCTE) ने 2010 में अनिवार्य कर दिया था। केंद्र सेंट्रल TET और राज्य स्टेट TET करवाते हैं।
- NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को TET क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल कर दिया था।
- NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया।
- मद्रास HC बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी।
- उन्हें सेवा में बने रहने के लिए TET पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा।
- बाद में यह मामला अलग-अलग राज्यों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

पृष्ठ 01 का शेष...

मैं नौकरी देता जाऊंगा...

डॉ. रेखा पालावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रही। मेरे पिता किसान हैं। माता-पिता की मेहनत से मैं यहां तक पहुंची हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे ईमानदारी से निभाऊंगी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अंशु गुप्ता ने कहा- यह मेरे लिए खुशी का पल है। परीक्षा पारदर्शी तरीके से पूरी हुई है। आयुष विभाग लोगों तक आयुष चिकित्सा पद्धति पहुंचा रहा है। मैं अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूंगी। सरिता सोनी ने कहा- मेरा एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ है। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हुई। बेटियों को सम्मान और सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। एक्स-रे टेक्नीशियन अनुराग गौतम ने कहा- मैं सीएम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा करूंगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा- यह परिणाम मेरे माता-पिता के आशीर्वाद और यूपी सरकार की पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था का नतीजा है। 2017 से पहले यूपी की धारणा क्या थी? हर दूसरे दिन दंगा होता था और महीनों तक कर्फ्यू रहता था। युवाओं के सामने एक ओर कुआं और दूसरी ओर खाई थी। यूपी में नौकरी नहीं थी। युवाओं के लिए भयावह स्थिति थी। इससे उसके सपने टूटते थे।

इंदौर में राहुल गांधी...

उन्होंने स्टूडेंट्स से भी सेल्फी लेने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के चलते 55% स्कूल एमपी और यूपी में बंद होते हैं। हॉस्टल भी 100 में से 14 लोगों को मिल सकता है। जब सरकार शिक्षा में कम पैसा डालती है तो स्टूडेंट खतरे में होता है। राहुल ने दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे की क्लिप दिखाई और कहा- ये है रिजल्ट सरकारी इंफ्रास्टक्चर न होने का। दिवंगत बच्चे के दादा बोले- मेरा पोता दिल्ली में पढ़ना गया था। वह 18 साल का था। वह चला गया। राहुल बोले- अगर अच्छी फैसिलिटी होती तो आज ये नहीं होता। राजगढ़ की सपना गुर्जर ने कहा- मार्च 2019 में कांग्रेस सरकार ने 14 फीसदी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी किया था। यह पूरे प्रदेश में लागू भी है। सरकार बदलते ही बीजेपी सरकार ने हमारे 13 फीसदी पद पर कोर्ट का हवाल देकर हमारी सारी नियुक्त होल्ड कर दी है। पिछले 8 साल से हमारे 10 हजार पदों पर होल्ड नाम का राक्षस बैठा है। सतना के रहने वाले अखिल भारती क्रांति ने कहा- मैं एमपीपीएसी का छात्र हूं। यहां हालात ऐसे हैं कि पिछले 8 साल से जितने भी पदों पर भर्ती होती है उसमें 13 फीसदी पद होल्ड कर दिए जाते हैं। प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। मेरे जैसे 4 लाख 87 हजार बच्चे होल्ड हैं। कोर्ट का बहाना देकर सरकार रोक देती है। 2018 में कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया, तब से ही यह होल्ड है। हम लोग ओवर एज हो गए। नर्सिंग स्टूडेंट याशिका दानी ने कहा– मैंने 2020 में एडमिशन लिया था, सोचा था कि मेरा कोर्स चार साल में पूरा हो जाएगा। 2026 चल रहा है और मैं अभी भी थर्ड ईयर में हूं। न रिजल्ट आया है, न फोर्थ ईयर के एग्जाम हो रहे हैं।

'रोजगार बढ़ाने के...

सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही। साथ ही आपके माता-पिता और आपके परिजन की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इको सिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम है। और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप टियर2 और टियर3 शहरों में हैं। कुछ ही दिन पहले ब्रिक्स समिट खत्म हुआ है। भारत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ब्रिक्स का सहयोग सिर्फ सरकारों तक ही सीमित न रहे; बल्कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स, किसान, महिलाएं और युवा भी इस साझेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हों। इसी सोच के साथ 'ब्रिक्स कनेक्ट' और 'ब्रिक्स MSME कोऑपरेशन पोर्टल' जैसी पहल शुरू की गई हैं। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार का लगातार ध्यान युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है।

रेजीनगर में ममता...

नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद और रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ममता बनर्जी ने TMC का नाम और 'जोड़ा घास फूल' चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने शुक्रवार को अपनी याचिका में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को पक्षकार बनाया है। इससे एक दिन पहले 17 सितंबर को चुनाव आयोग ने दोनों TMC गुटों को मूल नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोकते हुए अलग-अलग नाम और सिंबल दिए थे। अब दोनों गुट उपचुनाव में नई पार्टी नाम और सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। ममता गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल प्लेयर' सिंबल मिला, जबकि अरूप रॉय गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' सिंबल आवंटित किया गया। TMC में विवाद मई के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद शुरू हुआ।

डूसू चुनाव में एबीवीपी...

उनके पिता चाहते थे कि वह UPSC की तैयारी करें, लेकिन शौकीन छात्र राजनीति में आना चाहते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो कैंपस हैं। साउथ और नॉर्थ कैंपस लगभग 15 किमी की दूरी पर बने हैं। दोनों कैंपस मिलाकर DU में 91 कॉलेज आते हैं, लेकिन DUSU के चुनावों में DU के सभी कॉलेज वोट नहीं कर सकते हैं। DUSU में सिर्फ 52 कॉलेज और फैकल्टी ही सीधे तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। सेंट स्टीफंस, लेडी श्री राम और जीसस एंड मैरी जैसे कुछ बड़े कॉलेज भी DUSU का हिस्सा नहीं हैं। 18वें राउंड की काउंटिंग के बाद ABVP के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव पद पर आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष पद पर यश डबास को 21,109 और NSUI के विजय शंकर मीणा को 20,554 वोट मिले हैं। सचिव पद पर रिया छावड़ी को 18,366 और NSUI की नम्रता चौधरी को 13,451 वोट मिले हैं।

लखनऊ में बैठकर...

पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। मुख्य आरोपी शिवा उर्फ प्रियांशु कुशवाहा फरार है। वह गुजरात का रहने वाला है। अलीगंज के रिध्या प्लाजा में NEXOLANE SOLUTION नाम से सेंटर चल रहा था। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को 18 से 30 हजार रुपए महीने सैलरी दी जाती थी। उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी मुफ्त थी। यहां विदेशी नागरिकों के ऑनलाइन डेटा को ट्रैक किया जाता था। ठगी के लिए उनके कंप्यूटर या मोबाइल पर फर्जी पॉप-अप और हैकिंग का अलर्ट भेजा जाता था। डर की वजह से पॉप-अप पर दिए गए नंबर या विकल्प के जरिए पीड़ित जब कॉल सेंटर में फोन करता था। तो आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट का एजेंट या ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट बताकर बात करते थे। वे कंप्यूटर की समस्या ठीक करने का झांसा देकर UltraViewer जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते थे। इसके बाद फर्जी सिक्योरिटी स्कैन किया जाता था। पीड़ित को बताया जाता था कि उसके कंप्यूटर से पोर्नोग्राफी वेबसाइट खोली गई हैं।

शूटर मनु के साथ पवन सहरावत तिरंगा थामेंगे, फ्लैग मार्च जारी

एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी शुरू

समारोह

नागोया, एजेंसी

एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। नागोया के पालोमा मिजुहो स्टेडियम में म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ समारोह का आगाज हुआ। सेरेमनी से पहले जापानी बॉय बैंड INI ने भी प्रस्तुति दी। भारत की ओर से शूटर मनु भाकर और सीनियर कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत तिरंगा थामेंगे। शॉटपुटर तजिंदरपाल सिंह तूर को अब तक भारतीय किट नहीं मिलने के कारण उन्हें ध्वजवाहक की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। एशियन गेम्स में 45 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी 43 खेलों में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। भारत ने इस बार 503 खिलाड़ियों का दल भेजा है। भारत की क्विंसी डिसूजा एशियन गेम्स के पहले दिन शनिवार को टेकबॉल महिला एकल सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई की सुमाया से हार गईं। वे फाइनल के बेहद करीब थीं। मुंबई की 24 साल की डिसूजा ने पहला गेम 12-7 से जीता। लेकिन, सुमाया ने अगले दो गेम 9-12, 12-7 से जीत लिए। क्विंसी बॉन्ज मेडल के लिए 20 सितंबर को जापान की यूइना साकामोतो से खेलेंगी। जोकि विमेंस सिंगल्स रैंकिंग में 7वें नंबर की खिलाड़ी हैं। भारत ने हांगझोउ पिछले एशियन गेम्स में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 107 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड शामिल थे। टीम को शूटिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, क्रिकेट और वेटलिफ्टिंग समेत कई खेलों में मेडल की उम्मीद रहेगी।

ओपनिंग सेरेमनी से पहले जापानी बॉय बैंड INI ने परफॉर्मेंस दी।

पालोमा मिजुहो स्टेडियम में सेरेमनी शुरू

गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी पालोमा मिजुहो स्टेडियम, नागोया में हो रही है। जापान तीसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में इन खेलों का आयोजन हुआ था।

> भारत ने पिछले एशियन गेम्स की तुलना में इस बार छोटा दल भेजा है। 2022 में चीन के हांगझोउ में हुए एशियन गेम्स में भारत के 661 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इनमें 333 मेंस और 328 विमेंस थीं।

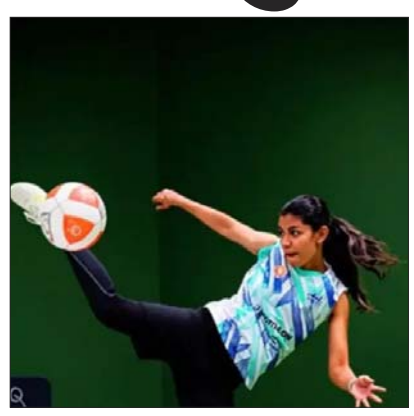

ऋषभ पंत की फैंस से अपील- खिलाड़ियों को सपोर्ट करें

ऋषभ पंत ने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वे गेम्स देखने को लेकर काफी उत्साहित हैं। साथ ही पंत ने फैंस से अपील की है कि खिलाड़ियों के साथ खड़े रहें और उन्हें सपोर्ट करें।

एशियन गेम्स बैडमिंटन ड्रॉ जारी जापान से भिड़ने की संभावना

नई दिल्ली, एजेंसी

एशियन गेम्स के बैडमिंटन टीम इवेंट के ड्रॉ में भारतीय मेंस टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। टीम क्वार्टरफाइनल में जापान से भिड़ सकती है।

सिल्वर मेडल विजेता भारतीय मेंस टीम के सेमीफाइनल में चीन या कोरिया से मुकाबले की संभावना है। भारत, जापान, चीन और कोरिया एक ही हाफ में हैं।

भारतीय विमेंस टीम अपने अभियान की शुरुआत कजाकिस्तान के खिलाफ करेगी। वह क्वार्टरफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान से भिड़ सकती है।

भारत को आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य सेन को कोडाई नाराओका और आयुष को यूशी तनाका को हराना होगा। सात्विक-चिराग की जोड़ी का मुकाबला होकी-कोबायाशी से हो सकता है।

भारतीय मेंस टीम पिछली बार चीन से 2-3 से हारकर गोल्ड मेडल से चूक गई थी। इस बार उसका सेमीफाइनल में ही चीन से मुकाबला हो सकता है।

हालांकि, धीमे कोर्ट पर जापान भारत के लिए मुश्किल चुनौती बन सकता है। जापान के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट कोडाई नाराओका हैं।

मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और ताइवान को ड्रॉ के दूसरे हाफ में रखा गया है। भारत के विमेंस टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जापान से भिड़ने की संभावना है। मुकाबले में अकाने यामागुची और पीवी सिंधु आमने-सामने हो सकती हैं। उन्नति हुड्डा का सामना टोमोका मियाजाकी से हो सकता है, जबकि ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को जापान की टॉप जोड़ी की चुनौती मिलेगी।

एशियाड में 100 मेडल भी नहीं जीतेगा भारत

नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भारतीय ओलिंपिक संघ और टॉप्स की रिपोर्ट में दावा, 97 मेडल जीतेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय खिलाड़ी जापान में चल रहे एशियन गेम्स में 100 मेडल के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बार करीब 97 मेडल मेडल जीतने की उम्मीद है।

यह दावा नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन (NSA), इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) और साई की टारगेट ओलिंपिक पोडियम (टॉप्स) स्कीम की अंतरिक रिपोर्ट में किया गया है।

भारतीय ओलिंपिक संघ के एक सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर मेडल की संभावनाओं का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस बार भारत के सिल्वर मेडल की संख्या बढ़ेगी। जबकि गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल कम होंगे। अनुमान के अनुसान भारत 20वें एशियाड में 25 गोल्ड मेडल जीतेगा। उसे 42 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मिलेंगे। भारत ने हांगझोऊ एशियन गेम्स में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत 107 मेडल जीते थे। हालांकि, एक मेडल डोपिंग नियमों के कारण वापस ले लिया गया था।

रिपोर्ट में अनुभवी प्लेयर्स से ज्यादा युवाओं से ज्यादा उम्मीद लगाई गई है। शूटिंग में मनु भाकर से ज्यादा उम्मीद ईशा सिंह से हैं। स्क्वॉश जोशना चिनप्पा के ज्यादा अनाहत सिंह पर भरोसा है। बैडमिंटन में सिंधु से ज्यादा भरोसा आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन से है। शूटिंग में पलक-मुकेश की जोड़ी से मेडल होप। जूडो में अस्मिता डे से भी मेडल की उम्मीद है। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह से पदक की उम्मीद है।

बीसीसीआई को चिट्ठी, 4 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो रहा, बोर्ड को नए सिलेक्टर की तलाश

अगरकर चीफ सिलेक्टर के पद से हटना चाहते हैं

दावा

नई दिल्ली, एजेंसी

अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर के पद से हटना चाहते हैं। यह दावा न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। 48 साल के अगरकर ने BCCI को शुक्रवार को एक लेटर लिखकर बताया कि वे इस पद पर आगे जारी नहीं रहना चाहते।

अगरकर का मौजूदा कार्यकाल 4 अक्टूबर में खत्म हो रहा है। उन्होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक अपना कार्यकाल बढ़ाने की इच्छा जताई थी। वे जुलाई 2023 में सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने थे। अगर अगरकर का कार्यकाल खत्म होता है, तो BCCI तुरंत नया चयनकर्ता प्रमुख नियुक्त नहीं कर सकेगा। बोर्ड को पहले पद के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के कारण नए अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लग सकता है। अगरकर की जगह पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। बैठक के बाद BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था, 'हमारे पास अभी 15 दिन हैं। क्रिकेट की दुनिया में 15 दिन बहुत लंबा समय होता है। हम सही समय पर फैसला लेंगे।'

लॉर्ड्स में रोहित शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद सवाल उठे थे

लॉर्ड्स वनडे से पहले रोहित शर्मा प्रकरण के बाद से अगरकर के पद पर सवाल उठे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक सिलेक्टर ने रोहित शर्मा को बताया था कि वे टीम की योजनाओं में नहीं हैं। रोहित ने शतक लगाकर खुद को साबित किया। वे लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। इसके बाद BCCI को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था।

> बीसीसीआई की एनुअल जरनल मीटिंग में बोर्ड के पदाधिकारियों को सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया। माना जा रहा था कि इस बैठक में अगरकर के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा।

मनोरंजन

बोलीं- फिल्मों से निकाले जाने पर बहुत तकलीफ होती थी, खुद से सवाल करती थी

रिजेक्शन और रिप्लेसमेंट के बाद तारा सुतारिया ने बनाई पहचान

नई दिल्ली। बॉलीवुड में पहचान बनाने का सपना लेकर आने वाले हर कलाकार का सफर एक जैसा नहीं होता। कुछ को फिल्मी परिवार का सहारा मिलता है, तो कुछ हुनर और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अभिनेत्री तारा सुतारिया का सफर भी ऐसा ही है। अभिनय के साथ संगीत और गायकी में रुचि रखने वाली तारा ने टेलीविजन से शुरुआत की और 2019 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बड़े पर्दे पर कदम रखा।

फिल्मों में आने से पहले तारा सुतारिया टेलीविजन पर काम कर चुकी थीं। उन्होंने डिज्नी चैनल के शो 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' और 'ओए जस्सी' में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने 'बिग बड़ा बूम' से बतौर गायिका और परफॉर्मर टीवी करियर की शुरुआत की थी। वह 'एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा' और 'बेस्ट ऑफ लक निक्की' जैसे टीवी शोज में भी नजर आईं। टेलीविजन पर काम करने से उन्हें कैमरे के सामने अभिनय और दर्शकों से जुड़ने का अनुभव मिला। यह उनके करियर का शुरुआती चरण था, जिसने उन्हें फिल्मों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार किया। तारा का एक और हुनर गायकी था। उन्होंने PTI को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह फिल्मों में गाना चाहती थीं और भविष्य में बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाना चाहती हैं। साल 2019 तारा सुतारिया के करियर के लिए महत्वपूर्ण रहा। इसी साल उन्होंने पुनीत मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया।

तारा सुतारिया 2014 में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के टैलेंट रियलिटी शो 'एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा' में गायिका और परफॉर्मर के रूप में नजर आई थीं।

> तारा का फिल्मी सफर कई अनुभवों से गुजर चुका है। उन्होंने रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में काम किया और अपूर्वा जैसी सर्वाइवल थ्रिलर में मुख्य भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें फिल्मों से रिप्लेस किए जाने और इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बचपन से ही संगीत और मंच से जुड़ाव

तारा सुतारिया का जन्म 19 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ। उन्हें बचपन से संगीत और परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि थी। उन्होंने कम उम्र में गायन की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। संगीत के अलावा नृत्य और मंच पर प्रस्तुति देने का भी अनुभव रहा है। वह लगभग 15 साल की उम्र से मंच पर प्रस्तुति दे रही थीं। तारा हमेशा गायिका और परफॉर्मर बनना चाहती थीं। बॉलीवुड में अभिनय का मौका मिलने के बाद भी संगीत उनके लिए महत्वपूर्ण बना रहा। तारा ने म्यूजिकल थिएटर में भी काम किया। वह रैल पदमसी के प्रोडक्शन 'ग्रीस' और अश्विन गिडवानी के 'ब्लेम इट ऑन यशराज' जैसे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स से जुड़ी रहीं। इस अनुभव से उन्हें मंच पर आत्मविश्वास और दर्शकों के सामने प्रस्तुति का अवसर मिला।

कटरीना की बॉडी शेमिंग पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी-खुशबू सुंदर

पूर्व सांसद बोलीं- शरीर, उम्र के फैसलों के लिए सफाई क्यों देनी चाहिए? ऋतिक ने भी बचाव किया

नई दिल्ली। कटरीना हाल ही में अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन का हिस्सा बनीं, जहां उनके बढ़े हुए वजन का मुद्दा बना दिया गया। पोस्ट प्रेग्नेंसी बढ़े हुए वजन के बीच हो रही ट्रोलिंग पर अब पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्ट्रेस का बचाव किया और ट्रोलर्स की आलोचना की। प्रियंका चतुर्वेदी ने आधिकारिक X अकाउंट (पहले ट्विटर) पर लिखा है, 'प्रिय महिलाओं, आपका वजन बढ़ा है या घटा है, आपकी उम्र कितनी है, आप कैसी दिखती हैं, आपका शरीर कैसा है या आपकी स्किन कैसी है, इनमें से किसी भी चीज का हिसाब आपको उन लोगों को देने की जरूरत नहीं है, जिनके पास दूसरों की जिंदगी पर कमेंट करने के अलावा कोई काम नहीं है।' भारतीय जनता पार्टी की नेता और साउथ एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने कटरीना का बचाव करते हुए लिखा है, 'आखिर किसी महिला की उम्र को हमेशा सार्वजनिक चर्चा का विषय क्यों बना दिया जाता है?

रणबीर कपूर ने विसर्जन में लगाया जय श्री राम का जयकारा, सुनीता-गोविंदा अलग-अलग बप्पा के विसर्जन में पहुंचे

बेटी राहा का चेहरा छिपाती दिखीं आलिया

नई दिल्ली। रणबीर कपूर ने शुक्रवार को पत्नी आलिया भट्ट और मां नीतू के साथ गणेश विसर्जन किया। आलिया भट्ट इस दौरान बेटी राहा का चेहरा छिपाती नजर आईं। वहीं रणबीर ने परिवार के साथ गणपति बप्पा मोरया और जय श्री राम का जयकारा लगाया। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी मुंबई स्थित घर में गणेश पूजा का आयोजन किया, जिसमें फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियां पहुंचीं। गोविंदा एकता कपूर के घर पहुंचे, जबकि पत्नी सुनीता, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के घर गणेश आरती का हिस्सा बनीं।

विसर्जन के समय आलिया भट्ट ने बेटी राहा को गोद में उठा रखा था और उसका चेहरा पूरी तरह छिपाकर रखा। लौटते हुए बेटी का चेहरा न दिखे, इसलिए आलिया उल्टे पांव पीछे गईं। कुछ देर बाद उन्होंने राहा के बिना रणबीर और नीतू सिंह के साथ तस्वीरें क्लिक करवाईं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के घर गणपति सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी हैं। जबकि कुछ महीनों पहले तक सुनीता की कृष्णा के परिवार से अनबन थी। सुनीता ने इस दौरान कपिल शर्मा के साथ तस्वीरें क्लिक करवाई हैं। अंकिता लोखंडे ने भी शुक्रवार को बप्पा का विसर्जन किया। इससे पहले बप्पा की आरती करते हुए अंकिता लोखंडे काफी एनर्जेटिक नजर आईं।

एकता कपूर के घर हुई गणेश आरती में पहुंचे सेलेब्स

टेलीविजन क्वीन और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी अपने घर में गणेश पूजा का आयोजन किया, जिसमें फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। गोविंदा बेटे यशवर्धन के सा आरती में पहुंचे। अंकिता लोखंडे, पति विक्की जैन के साथ पहुंचीं, वहीं आयुष्मान खुराना, चंकी पांडे समेत कई सेलेब्स इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने।

ललित मोदी पर बनेगी बायोपिक

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक ललित मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनने जा रही है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बायोपिक को साजिद नाडियाडवाला अपने बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का काम पूर्व टीवी एग्जीक्यूटिव और प्रोड्यूसर स्नेहा रजनी कर रही हैं। यह फिल्म ललित मोदी के शुरुआती जीवन, IPL की शुरुआत, उनकी सफलता और बाद में जुड़े विवादों पर आधारित होगी।

कुछ समय पहले रणवीर सिंह ने ललित का रोल निभाने में दिलचस्पी दिखाई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने भी पुष्टि की थी कि रणवीर उनका रोल निभाना चाहते हैं। ललित करीब 16 साल से लंदन में रह रहे हैं।

मेकर्स इस बायोपिक में ललित मोदी की सिर्फ हेडलाइंस और विवादों पर ध्यान देने के बजाय उनके निजी जीवन और करियर के अलग-अलग पहलुओं को दिखाना चाहते हैं।

ट्रम्प ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेकर डील की

समझौता

आजादी के बाद भी अमेरिकी सेना वही रहेगी, 9 महीने पहले कब्जे की धमकी दी थी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ेगी और रूस-चीन जैसे गैर-नाटो देशों को वहां सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं होगी।

यह समझौता ग्रीनलैंड के भविष्य में आजाद होने की स्थिति में भी लागू रहेगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि समझौते से डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता बरकरार रहेगी। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है।

ट्रम्प ने जनवरी में कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे पहले टर्म से ही ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात करते रहे हैं।

जनवरी में अमेरिका-डेनमार्क के बीच बढ़ा था तनाव

ट्रम्प लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ जोड़ने की इच्छा जाहिर करते रहे हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने इस विचार को खारिज किया है।

फिलहाल वहां अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस मौजूद है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ग्रीनलैंड का दौरा कर पुराने सैन्य ठिकानों को दोबारा खोलने की संभावनाएं भी देखी हैं। अब नए समझौते में गैर-नाटो देशों के सैन्य अड्डे और सैन्य मौजूदगी को रोकने की बात कही गई है। ग्रीनलैंड लंबे समय से ज्यादा स्वायत्तता और आजादी की मांग करता रहा है। वहां कई लोग इसे स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। अभी इसकी रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है।

ट्रम्प प्रशासन की चिंता यह रही है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड स्वतंत्र देश बन जाता है, तो अमेरिका की मौजूदा सैन्य पहुंच पर क्या असर पड़ेगा। नए समझौते में इस स्थिति को भी शामिल किया गया है।

इस साल जनवरी में दोनों पक्षों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। डेनमार्क की सेना ने अमेरिकी हमले की स्थिति में ग्रीनलैंड के एयरफील्ड को नष्ट करने तक की योजना बनाई थी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैनिक भी भेजे थे।

रूस-चीन नहीं बना सकेंगे सैन्य अड्डा

समझौते की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारें अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस पर हस्ताक्षर करेंगी। इसे लागू करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संसदों की मंजूरी जरूरी होगी।

ट्रम्प के मुताबिक, समझौते में ग्रीनलैंड में अमेरिका के विरोधी देशों के सैन्य अड्डे बनाने पर रोक होगी। इसके अलावा, ग्रीनलैंड के संवेदनशील इलाकों में कोई बड़ा निवेश अमेरिका की लिखित मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, नाटो से बाहर के देशों को ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा या सैन्य मौजूदगी रखने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीनलैंड नाटो क्षेत्र में आता है। ऐसे में रूस और चीन जैसे गैर-नाटो देशों की सैन्य मौजूदगी रोकने वाला यह प्रावधान अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है।

1951 से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी

ग्रीनलैंड में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी नई नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहली बार यहां सैन्य मौजूदगी बनाई थी। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक रक्षा समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य ठिकाने चलाने और अपनी सेना की गतिविधियां करने की काफी आजादी मिली। इस समझौते में नाटो देशों की सेनाओं को भी ग्रीनलैंड में पहुंच की अनुमति थी। हालांकि, रूस या चीन जैसे देशों की सैन्य मौजूदगी पर साफ रोक नहीं थी।

> ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उनके मुताबिक, वहां कई ऐसी जगहें हैं जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाई जा सकती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के ग्रीनलैंड में एक दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकाने थे। बाद में इनमें से ज्यादातर बंद कर दिए गए।

फास्ट न्यूज

ईरान में 'हिजाब कानून' को खुली चुनौती

तेहरान। ईरान में कानून के तहत हिजाब पहनना अनिवार्य है। लेकिन हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाएं बिना हिजाब या स्कार्फ पहने ही 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेती नजर आईं। ईरान से सामने आए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। शुक्रवार को वेलायत पार्क में हुई 'तेहरान 10K' दौड़ में कई महिलाओं को बिना सिर ढके दौड़ते देखा गया।

सितंबर 2027 तक एच-1इ वीजा फीस में बढ़ोतरी रहेगी बरकरार

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में की गई सख्ती को अगले एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसके तहत, अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक आईटी और अन्य क्षेत्रों के विदेशी पेशेवरों को अब $100,000 का अनिवार्य शुल्क देना होगा। व्हाइट हाउस की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, सितंबर 2025 में लागू किए गए ये कड़े नियम अब 21 सितंबर, 2027 तक जारी रहेंगे। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बाजार के हालात अभी सुधरे नहीं हैं ।

एआई की एक गलती से यूएस-चीन में छिड़ने वाला था युद्ध

वाशिंगटन। ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट में तबाही का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था, जो अमेरिका और चीन को सीधे युद्ध के मुहाने पर ले आया। खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि मध्य पूर्व के समुद्र में तैर रहा एक चीनी जहाज परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े खतरनाक उपकरण ले जा रहा है।

गोल्ड ईटीएफ में एक साल में 35% का रिटर्न मिला

इसके जरिए कम पैसों में सोने में निवेश

नई दिल्ली, एजेंसी

निवेशकों इन दिनों सोने में निवेश लुभा रहा है। अगस्त में गोल्ड ETF में निवेश जुलाई के 1,558 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,596 करोड़ रुपए रहा। गोल्ड ETF ने बीते एक साल में 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटजी हेड क्रिस वुड का मानना है कि सोने के दाम में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो गोल्ड ETF के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सोने के गिरते-चढ़ते भावों पर बेस्ड होते हैं। गोल्ड ETFs की खरीद-बिक्री शेयर की ही तरह BSE और NSE पर की जा सकती है। हालांकि, इसमें आपको सोना नहीं मिलता। आप जब इससे निकलना चाहें तब आपको उस समय के सोने के भाव के बराबर पैसा मिल जाएगा।

गोल्ड ETF खरीदने के लिए आपको अपने ब्रोकर के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोलना होता है। इसमें NSE पर उपलब्ध गोल्ड ETF के यूनिट आप खरीद सकते हैं और उसके बराबर की राशि आपके डीमैट अकाउंट से जुड़े बैंक अकाउंट से कट जाएगी। आपके डीमैट अकाउंट में ऑर्डर लगाने के दो दिन बाद गोल्ड ETF आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। ट्रेडिंग खाते के जरिए ही गोल्ड ETF को बेचा जाता है।

लाखों सैनिकों की ट्रेनिंग, हथियारों का जखीरा बढ़ा, युद्ध के लिए सिस्टम बदल रहा नाटो

रूसी खतरे के बीच यूरोप की 10 साल की तैयारी

कोपेनहेगन/वॉशिंगटन, एजेंसी

यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूरोप के नाटो देश अगले 10 साल में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर GDP का 5% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हथियार, सैनिकों की ट्रेनिंग, सैन्य ठिकाने, बंकर, अस्पताल और साइबर सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं मजबूत की जाएंगी।

रूस लगातार यूरोपीय देशों को चेतावनी दे रहा है। पिछले हफ्ते ब्रिक्स समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात करते हैं, तो इसे रूस के साथ युद्ध माना जाएगा।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भी यूरोपीय देशों से अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करने की मांग करते रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार और शनिवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में नाटो के 32 सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों की बैठक हुई। जर्मनी में 1979 में बनाए गए मेडिकल बंकरों को दोबारा इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। युद्ध या बड़े हमले की स्थिति में इनका इस्तेमाल घायलों के इलाज के लिए किया जाएगा। नॉर्वे भी अपने अस्पतालों को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। वहां 7 हजार बेड युद्ध में घायल सैनिकों और आम लोगों के इलाज के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी है।

2035 तक जीडीपी का 5% सुरक्षा पर खर्च होगा

नाटो देशों ने रक्षा और सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है। 2035 तक GDP का 5% इस क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें 3.5% पैसा सीधे सेना, हथियारों और सैन्य क्षमता बढ़ाने पर खर्च होगा। बाकी 1.5% सड़कों, कम्युनिकेशन, साइबर सुरक्षा और ऐसी दूसरी सुविधाओं पर लगाया जाएगा, जो युद्ध या किसी बड़े संकट के समय काम आ सकती हैं।

यानी यूरोप की तैयारी सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। अगले करीब 10 साल में सैनिकों की ट्रेनिंग, सैन्य ठिकानों और युद्ध के समय काम आने वाली जरूरी सुविधाओं पर भी खर्च बढ़ाया जाएगा।

ट्रम्प लंबे समय से यूरोप से ज्यादा खर्च करने को कह रहे

नाटो देशों का रक्षा खर्च बढ़ाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का दबाव भी एक वजह है। ट्रम्प लंबे समय से यूरोपीय देशों से अपनी सुरक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। पिछले साल हेग में हुए नाटो सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2035 तक GDP का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया था।

इसके साथ यूक्रेन की जंग ने भी यूरोप की सैन्य जरूरतों को सामने ला दिया है। युद्ध में ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है।

---

100 से ज्यादा लोग घायल, विस्फोटक से भरी गाड़ी मस्जिद से टकराई थी

पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में अब तक 31 लोगों की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में मस्जिद के पास पुलिस परिसर पर हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। मृतकों में 16 पुलिसकर्मी शामिल हैं। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हमला शुक्रवार दोपहर हुआ। उस समय पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से भरी कार लेकर पहुंचे थे और कार मस्जिद की दीवार से टकराकर धमाका कर दिया था।

जहां हमला हुआ वह कोई सामान्य पुलिस चौकी नहीं थी। कोहाट का ओल्ड पुलिस लाइंस परिसर जिला स्तर का बड़ा पुलिस मुख्यालय है।

यहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाला काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD), स्पेशल ब्रांच और पुलिस की दूसरी इकाइयों के दफ्तर हैं। यही वजह है कि हमलावरों ने पुलिस परिसर को निशाना बनाया। हमले के बाद इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। यह संगठन हाफिज गुल बहादुर से जुड़े गुट के नेतृत्व वाला बताया जा रहा है।

शुरुआती रिपोर्टों में एक अन्य संगठन की ओर से भी जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आया था। इसलिए हमले के पीछे किस गुट की भूमिका थी, इसे लेकर अभी अलग-अलग दावे हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बढ़ रहे आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान से सक्रिय आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, अफगान की तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है।

पुलिस और हमलावरों के बीच गोलीबारी हुई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कुछ हमलावर अभी भी परिसर की स्पेशल ब्रांच की इमारत में छिपे हुए हैं। पुलिस और उनके बीच रात में गोलीबारी भी हुई। फिलहाल यह नहीं बताया गया कि कितने हमलावरों ने हमला किया था। शुक्रवार को 6 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी।

> तेज धमाके से मस्जिद और परिसर की दूसरी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद की दीवारें गिर गई थी और कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में ईंट-पत्थर और टूटी हुई दीवारें दिखाई दीं।

कोहाट पुलिस लाइन में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आईजी के हाथ में चोट लगी।

चीनी त्योहारों से पहले सस्ती होगी स्टॉक लिमिट 15 से बढ़ाकर 30 दिन की

सरकार ने कारोबारियों से कहा- लोगों को सस्ती चीनी दें

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और त्योहारों से पहले कीमतें काबू करने के लिए बल्क कंज्यूमर्स के लिए स्टॉक लिमिट बढ़ाकर 30 दिन कर दी है।

सरकार के इस कदम से मिठाइयों, बेकरी और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को त्योहारों के दौरान चीनी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्क कंज्यूमर वे कंपनियां या औद्योगिक इकाइयां हैं, जो कच्चे माल के रूप में हर महीने 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करती हैं।

अभी ये कंपनियां अपनी सिर्फ 15 दिन की जरूरत के बराबर स्टॉक रख सकती थीं। सरकार ने करोबारियों से कहा है कि लोगों को सस्ती चीनी दें।

सरकार ने कहा है कि स्थानीय बाजार से आप 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकते। अगर 15 दिन से ज्यादा यानी 30 दिन तक चीनी रखनी है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक सिर्फ विदेश से मंगवाई गई यानी आयातित चीनी का ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि देश के स्थानीय बाजार में चीनी की कोई कमी न हो और कीमतें नियंत्रण में रहें। चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। अब चीनी का इस्तेमाल करने वाली सभी बड़ी कंपनियों को हर शुक्रवार को खाद्य मंत्रालय के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर बताना होगा कि उनके पास कितना स्टॉक बचा है। फैक्ट्रियों में चीनी 25% सस्ती हो गई है, लेकिन दुकानों पर इसकी कीमत सिर्फ 10% ही घटी है।

तैयारी : जंग के बाद सबसे बड़ी रैली, 6 लाख ने हथियार ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया

ईरान- सरकार के बुलावे पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे

तेहरान, एजेंसी

ईरान में शुक्रवार को सरकार के बुलावे पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी तेहरान में हुई यह रैली युद्ध शुरू होने के बाद सरकार की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी।

लोगों ने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने और सैन्य ट्रेनिंग लेने की तैयारी जताई। सरकार ने इस अभियान का नाम 'जांफदाए ईरान' रखा है। इसका मतलब है- ईरान के लिए जान तक देने को तैयार लोग।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, 6 लाख से ज्यादा लोग अब तक सैन्य ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख ने दावा किया कि ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। रैली में राष्ट्रपति मसूद पजशकियान, सैन्य कमांडर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कुछ लोगों ने अमेरिका और इजराइल के झंडों को पैरों से रौंदा। यहां 'अमेरिका की मौत' और 'इजराइल की मौत' जैसे नारे भी लगाए गए। ली में शामिल 24 साल की मरजिएह अफागी अपने छोटे बच्चे और पति के साथ पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बताना चाहती हैं कि ईरान के लोगों को अपने देश को लेकर उनकी धमकियों से डर नहीं लगता।

तेहरान में 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे

सरकारी प्रसारक के मुताबिक, शुक्रवार सुबह तेहरान की सड़कों पर 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। कई लोग सैन्य वर्दी में थे और हाथों में ईरान के झंडे लिए हुए थे। सरकार की योजना इन लोगों को असॉल्ट राइफल चलाने समेत सीमित सैन्य ट्रेनिंग देने की है। इसके बाद इन्हें देश की सुरक्षा में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लोगों को देश की सुरक्षा में मदद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज मिलिशिया ईरान की एक सरकार समर्थक अर्धसैनिक संगठन है। इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी प्रदर्शनों को रोकने में इस्तेमाल होता रहा है।

बांग्लादेश: अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए जगह तक नहीं

फर्श पर हो रहा इलाज, 18 दिनों में 79 मौतें

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश इन दिनों डेंगू की मार झेल रहा है। राजधानी ढाका और उसके आसपास के इलाकों में इसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मरीजों को अस्पताल में जगह तक नहीं मिल पा रहा है।

अस्पतालों में बेड कम पड़ जाने के कारण लोग फर्श और बरामदों पर अपना इलाज करान के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य निदेशालय (DGHS) के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक 59000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जबकि अकेले सितंबर के शुरुआती 18 दिनों में 79 लोगों की जान जा चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार ढाका के प्रसिद्ध मुग्दा जनरल अस्पताल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इस अस्पताल के डेंगू वार्ड की कुल क्षमता सिर्फ 38 बेड की है, लेकिन वहां 145 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। स्थिति यह है कि एक ही बेड पर कई मरीज लेटे हैं, और जो जगह बच रही है वहां फर्श और बरामदे में मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है।

रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ ढाका ही नहीं, बल्कि नारायणगंज और अन्य जिलों से भी गंभीर हालत में मरीज यहां पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों और नर्सों का कहना है कि भारी भीड़ के कारण मरीजों की सही से देखभाल करने और आपातकालीन सेवाएं देने में काफी कठिनाई आ रही है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676